

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com



उदयपुर

Rashtradoot

फोन:- 2418945 फैक्स:- 0294-2410146

वर्ष: 33

संख्या: 88

प्रभात

उदयपुर, शुक्रवार 30 जनवरी, 2026

आर.जे. 7202

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

राजस्थान के वरिष्ठ नेतागण, खड़गे व राहुल गांधी से मिले दिल्ली में

मुलाकात का मुख्य ध्येय, ऐसा लगा है कि सचिन पायलट के खिलाफ वातावरण बनाना, जिससे डोटासरा अपने प्रदेशाध्यक्ष पद पर बने रहें व सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनने से रोका जा सके।

- रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 जनवरी। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ एक बैठक हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संदिग्ध रूप से अनुपस्थित रहे।

दिलचस्प बात यह है कि गहलोत एक महीने से अधिक समय से राजस्थान से गायब थे और लोगों द्वारा उनके ठिकाने को लेकर सवाल उठाए जाने के बावजूद, वे चुप्पी साधे हुए थे। हालांकि, दिल्ली में होने वाली बैठक से ठीक पहले आज सुबह अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें ठंडे स्थानों से दूर रहने और गर्म जलवायु में रहने की सलाह दी है, क्योंकि वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।

बैठक के दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि अशोक गहलोत कहाँ हैं, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहलोत को फोन मिलाया और फोन राहुल गांधी को दे दिया। राहुल ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, और उन्हें बताया गया कि गहलोत को निमोनिया हुआ था और वे मुंबई के

■ इस बैठक में अशोक गहलोत की अनुपस्थिति काफी चर्चित रही, हालांकि, बैठक से ठीक पहले गहलोत ने ट्वीट करके यह उजागर किया था कि वे मुम्बई में हैं तथा उन्हें निमोनिया हो गया था। अतः डॉक्टरों ने उन्हें हिदायत दी है कि ठंड से बचें और ऐसी गरम जगह पर रहें, जहाँ तापमान ज्यादा ठंडा न हो, बल्कि थोड़ा गरम हो।

■ गहलोत ने यही बात राहुल गांधी को दोहराई, जब राहुल ने उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, खड़गे द्वारा गहलोत को फोन मिलाने पर।

■ भंवर जितेन्द्र सिंह, प्रभारी रंधावा, कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल आदि की पूरी कोशिश है कि डोटासरा, प्रदेशाध्यक्ष बने रहें तथा सचिन पायलट को किसी भी तरह प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी से दूर ही रखा जा सके।

स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। गहलोत की बेटी मुंबई में रहती हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि गहलोत की अधिकांश संपत्ति मुंबई में ही है।

इस बैठक में सचिन पायलट के खिलाफ एक तरह से घेराबंदी भी देखने

को मिली, जहाँ वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा की जमकर तारीफ़ की, चाहे वह एसआईआर हो, बीएलए हो, मनरेगा हो या पार्टी संगठन व पार्टी को एकजुट रखने का मुद्दा हो।

डोटासरा और जूली की सराहना

करने वालों में भंवर जितेन्द्र सिंह, एआईसीसी प्रभारी रंधावा और संगठन मामलों के एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल प्रमुख रूप से शामिल थे।

सूत्रों के अनुसार, डोटासरा को मजबूत करने, उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर बनाए रखने और किसी भी तरह से यह सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि सचिन पायलट डोटासरा की जगह न ले सकें।

भंवर जितेन्द्र सिंह की गांधी परिवार तक सीधी पहुँच मानी जाती है और वे लगातार 'गुपचुप कैपेन' चलाने के लिए जाने जाते हैं। रंधावा, डोटासरा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, जिसके पीछे जाट समुदाय की बाँटिंग को भी कारण बताया जा रहा है। वहीं, वेणुगोपाल भी काफी समय से डोटासरा की प्रशंसा करते आ रहे हैं, ताकि प्रदेश कांग्रेस की कमान उनके पसंदीदा व्यक्ति के हाथों में बनी रहे।

रंधावा ने आगामी राज्यसभा चुनावों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीरजा मोदी स्कूल सीधे हाई कोर्ट में याचिका नहीं लगा सकता- सीबीएसई

जयपुर, 29 जनवरी। कक्षा चार की बालिका अमाया की मौत के मामले में नीरजा मोदी स्कूल की समबद्धता वापस लेने के मामले में सीबीएसई ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया है। हालांकि जवाब रिकॉर्ड पर नहीं आने के चलते, जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकल पीठ ने नीरजा मोदी स्कूल की याचिका पर शुक्रवार के लिए सुनवाई टाल दी।

सीबीएसई की ओर से अधिवक्ता एमएस राघव ने कहा कि स्कूल प्रशासन को सीधे हाईकोर्ट में याचिका पेश करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए, सीबीएसई चेयरमैन के समक्ष अपील पेश करनी चाहिए थी। घटना के बाद दो

■ सीबीएसई के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में कहा कि स्कूल को पहले सीबीएसई चेयरमैन के समक्ष अपील पेश करनी चाहिए।

सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। जिसकी रिपोर्ट में स्कूल में कई तरह की गंभीर खामियां होने की बात सामने आई है, जैसे स्कूल के बच्चे आइडो कार्ड नहीं लगाते, जिससे घटना के आधा घंटा बाद तक यह पता नहीं चला कि चौथी मंजिल से कूदने वाली छात्रा कौन थी। इसके अलावा, इमारत पर सेफ्टी नैट भी नहीं था। इसके होने से घटना रोकी जा सकती थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इकोनॉमिक सर्वे ने भी “डोमैस्टिक डिमांड” को ड्राइविंग इंजन माना

■ वित्त मंत्रालय द्वारा जारी “इकोनॉमिक सर्वे” के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, विश्व की इकॉनमी में अनिश्चितता तो जरूर ला रही हैं, पर, देश की इकॉनमी पर इसका खास असर नहीं हुआ है।

■ इसका मुख्य कारण है, देश की “डोमैस्टिक डिमांड” (आंतरिक खपत) के आंकड़े।

■ सर्वे के अनुसार, देश की इकॉनमी के शानदार प्रदर्शन व महँगाई की दर पर नियंत्रण के कारण सरकार अब इस स्थिति में है कि नये-नये प्रोजैक्ट ला सके व महत्वाकांक्षी स्कीम्स ला सके।

■ इससे, “डोमैस्टिक डिमांड” में उछाल आयेगा व नये रोज़गार की उपलब्धता बढ़ेगी।

की भावना पर असर डाल सकते हैं।”

घरेलू अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर आते हुए सर्वे ने कहा कि 2025-26 में घरेलू मांग ने आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाया। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अंतिम निजी उपभोग व्यय (पीएफसीई) की हिस्सेदारी बढ़कर 61.5 प्रतिशत हो गई।

सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया है कि खपत में मजबूती एक अनुकूल व्यापक आर्थिक माहौल को दर्शाती है, जिसकी विशेषता, कम महँगाई, स्थिर रोजगार स्थिति और बढ़ती वास्तविक क्रय शक्ति है।

इसके अलावा, मजबूत कृषि प्रदर्शन से समर्थित स्थिर ग्रामीण खपत और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण से शहरी खपत में धीरे-धीरे सुधार के कारण उपभोग मांग की गति व्यापक आधार पर बनी रही। इसी संदर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण में एक विरोधाभास नजर आता है।

आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तावना में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंतनागेश्वरन ने कठोपनिषद का हवाला देते हुए कहा है कि भविष्य की तृप्ति के लिए वर्तमान उपभोग पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शशि थरूर, राहुल गांधी व खड़गे से मिलने गए

लम्बी मुलाकात में शिकवे-शिकायतें दूर हुईं तथा थरूर ने एक ही आग्रह किया, राहुल उन पर विश्वास करें

- रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 जनवरी। लगातार सुर्खियों में रहे शशि थरूर की अंततः राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक लंबी और विस्तृत बैठक हुई, जिसमें कई गलतफहमियों को दूर किया गया। इस बैठक के बाद थरूर और राहुल गांधी के बीच एक कार्यकारी (वर्किंग) संबंध स्थापित हुआ।

यह बैठक केरल के कुछ सक्रिय कांग्रेस सांसदों की पहल का नतीजा थी, जिन्होंने के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात कर जोर दिया था कि राहुल गांधी और शशि थरूर को आपस में मिलकर अपने मतभेद सुलझाने चाहिए, अन्यथा कांग्रेस केरल खो सकती है।

एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने कहा कि अधिकांश गलतफहमियाँ के.सी. वेणुगोपाल ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते पैदा की थीं। उनका कहना था कि यदि राहुल गांधी

■ यह बैठक कांग्रेस के केरल से निर्वाचित सांसदों के जोर देने पर आयोजित की गई थी। इन सांसदों ने दबाव बनाया था कि राहुल गांधी व शशि थरूर अपने मतभेद साफ करके, नेतृत्व प्रदान करें राज्य में, अन्यथा कांग्रेस केरल में चुनाव हार जाएगी।

■ शशि थरूर ने राहुल से यह भी कहा कि उन्होंने केरल में एक आमसभा को संबोधित करते हुए, थरूर का नाम भी नहीं लिया था, हालांकि वे मंच पर बैठे थे। राहुल ने जवाब दिया, उनको एक चिट दी गई थी, जिसमें वे नाम लिखे हुए थे, जिन्हें राहुल को संबोधित करना था, अपना भाषण शुरू करने से पहले। यह आम धारणा है, यह चिट में नाम न होना, वेणुगोपाल की शरारत थी।

■ राहुल गांधी ने उसी समय यह भी आदेश दिए कि प्रदेशाध्यक्ष को पाबंद किया जाए कि हर पीसीसी बैठक में थरूर को लाज़मी तौर पर आमंत्रित किया जाए।

अब भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वेणुगोपाल किस तरह अपनी

महत्वाकांक्षा, केरल का मुख्यमंत्री

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जद (एस) प्रमुख देवेगौड़ा प्रधानमंत्री से मिले

नयी दिल्ली 29 जनवरी। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने गुरुवार को यहाँ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने देश के विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात के बारे में

■ देवेगौड़ा राज्यसभा सदस्य हैं तथा उनका दल राजग का हिस्सा है।

जानकारी दी।

मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा , " एच.डी. देवेगौड़ा जी के साथ उत्कृष्ट बैठक हुई। उनके महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार सराहनीय हैं। भारत के विकास के प्रति उनका उत्साह भी समान रूप से प्रशंसनीय है।"

देवेगौड़ा जनता दल (एस) के प्रमुख हैं और अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। जनता दल (एस) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में होने के नाते केन्द्र में सरकार में भी भागीदार है।

नफरती बयानबाजी कर भारी कानूनी विवाद में पड़ सकते हैं असम के मु.मंत्री

-श्रीनंदन झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जनवरी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा अपने बयानों को लेकर विवाद में फंसेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से “मियां मुस्लिम” रिक्शा चालकों को कम पैसे देने के लिए कहा था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार “मियां” समुदाय को “काबू में रखने” के लिए उन्हें परेशान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे स्थानीय समुदाय पर हावी न हो सकें।

इससे पहले वे यह भी दावा कर चुके हैं कि विशेष पुनरीक्षण (स्पेशल रिवीजन) अभियान के दौरान पांच लाख मियां मुसलमानों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे।

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति विभिन्न राज्यों, खासकर असम चुनाव प्रचार का लगातार हिस्सा रही है। असम में 1980 के शुरुआती वर्षों में “जनसंख्यिकीय घुसपैट” के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन हुआ था। वर्ष 2014 में असम की एक रेली में नरेन्द्र मोदी, जो तब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, ने अवैध बांग्लादेशी

असम के मु.मंत्री हिमंत बिस्वा ने लोगों को मुस्लिमों को परेशान करने के लिए उकसाया

■ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बयान में लोगों से अपील की कि मुसलमानों को परेशान किया जाए ताकि वे कमजोर हो जाएं। उन्होंने तरीका भी बताया, जैसे मुस्लिम रिक्शा वाले को कम किराया दिया जाए।

■ ऐसी टिप्पणियाँ गैर जमानती, संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आती हैं और अगर यह बयान संवैधानिक पद पर बैठे किसी नेता, जैसे मुख्यमंत्री, का हो तो बेहद गंभीर मामला बनता है।

■ कांग्रेस की असम यूनिट ने इस संबंध में याचिका भी दायर की है।

प्रवासियों से कहा था कि वे अपना सामान बांधकर लौट जाएं। बारह साल बाद, केन्द्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद यह समस्या अब भी बनी हुई है।

जब असम में नैशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिजन्स (एन.आर.सी.) तैयार

किया गया, तब पाया गया कि 19 लाख अवैध प्रवासियों में से 11 लाख हिंदू थे। हैरानी की बात यह है कि भाजपा एनआरसी के इन निष्कर्षों को स्वीकार नहीं करती, लेकिन मौजूदा विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मियां समुदाय को निशाना बना रही है। इससे

विपक्षी भड़क गए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि यह अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित करने के लिए किया जा रही एक लक्षित और सांप्रदायिक कवायव है।

सभी सरकारों को अवैध प्रवासियों को हटाने का अधिकार है। लेकिन यह अलग बात है कि कोई मौजूदा मुख्यमंत्री किसी खास समुदाय को सजा देने की खुली बात करे और उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित करने की धमकी दे। इस तरह की बातें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हैं। साथ ही, यह बात भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के तहत भी आ सकती है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास या भाषा के आधार पर अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी, नफरत या वैमनस्य फैलाने को अपराध मानती है। यह अपराध संज्ञेय है, जमानत नहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अजित पवार के विमान का ब्लैक बॉक्स मिला

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैकबॉक्स बरामद हो गया है।

जांच में शामिल अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि दुर्घटनाग्रस्त

■ एएआईबी का जाँच दल बुधवार को बारामती में।

लीयरजेट 45 विमान का ब्लैकबॉक्स दुर्घटनास्थल से बरामद किया गया है। इस विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उनके एक निजी सुरक्षा अधिकारी तथा एक सहायक और चालक दल के दो सदस्यों की मौत हो गयी थी। एएआईबी के महानिदेशक के नेतृत्व में जांच दल बुधवार को ही बारामती पहुँच गया था। इसके साथ नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के तीन अधिकारियों की मुंबई की टीम भी जांच कर रही है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

●●●●

⊕

●●●●

⊕

●●●●

⊕

●●●●

⊕

●●●●

⊕

●●●●

⊕

●●●●

⊕

●●●●

⊕

●●●●

⊕

●●●●

CMYK

विचार बिन्दु

पुरुषार्थ से दरिद्रता का नाश होता है, जप से पाप दूर होता है, मौन से कलह की उत्पत्ति नहीं होती और सजगता से भय नहीं होता। –चाणक्य

परंपरा और तकनीकी मिलकर गढ़ रहे हैं नया राजस्थान

राजस्थान, जो कभी रेगिस्तानों और किलों की भूमि के नाम से जाना जाता था, आज परंपरा और तकनीकी के अनोखे संगम से एक नया स्वरूप धारण कर रहा है। यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत आधुनिक विज्ञान के साथ जुड़कर न केवल आर्थिक प्रगति को गति दे रही है, बल्कि युवा पीढ़ी को भी अपनी जड़ों से जोड़े हुए है।

यह संयोजन राजस्थान को वैश्विक पटल पर एक अनूठा राज्य बना रहा है, जहाँ ऊँटों के मेलों के साथ डिजिटल स्टार्टअप्स फल-फूल रहे हैं। परंपरागत हस्तशिल्प अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक रहे हैं, और प्राचीन लोकगीत डिजिटल संगीत ऐप्स में गूँज रहे हैं।

राजस्थान की परंपराएँ सदियों पुरानी हैं, जो लोककला, संगीत, नृत्य और वास्तुकला में झलकती हैं। यहाँ के त्योहार जैसे पुष्कर मेला या जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल रंग-बिरंगे परिधानों, कठपुतली नृत्य और भोपा गायकों से सजते हैं। महिलाएँ पनहारी गीत गाते हुए कुर्रें से पानी भरती हैं, जो उनकी दैनिक जीवन की कविता है। किले जैसे आमेर, मेहरानगढ़ और जैसलमेर का स्वर्ण किला पीले बलुआ पत्थरों से चमकते हैं, जो राजपूत शौर्य की गाथा कहते हैं।

इन परंपराओं में हस्तशिल्प का विशेष स्थान है। टाई-डाई, मिरर वर्क, ब्लॉक प्रिंटिंग और जरी कढ़ाई जैसी कला पीढ़ियों से चली आ रही है। बीकानेर की कठपुतलियाँ और जोधपुर की लकड़ी की नक्काशी पर्यटकों को लुभाती हैं। राजस्थानी व्यंजन जैसे दाल बाटी चूरमा कम पानी वाली जलवायु के अनुकूल हैं, जो स्थानीय कृषि पर आधारित हैं। ये परंपराएँ न केवल सांस्कृतिक पहचान हैं, बल्कि आजीविका का स्रोत भी। लेकिन बदलते समय में इन्हें तकनीकी से जोड़ना आवश्यक हो गया है।

तकनीकी क्रांति ने राजस्थान को तेजी से बदल दिया है। राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्रों का जाल बिछा है, खासकर फलोदी और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में, जहाँ सूरज की प्रचुरता का लाभ उठाया जा रहा है।चंबल और माही नदियों पर बांधों से सिंचाई और बिजली मिल रही है, जो कृषि को आधुनिक बना रही है। जयपुर और जोधपुर में आईटी हब विकसित हो रहे हैं, जहाँ स्टार्टअप्स फल-फूल रहे हैं।

सौमेट उद्योग में राजस्थान देश में प्रथम है। लाखेरी और बूंदी के अलावा वर्तमान में सभी सीमेंट कारखाने अब उन्नत तकनीक से चलते हैं। कान्च उद्योग भी फलोदी, जयपुर और धौलपुर में पनप रहा है। डिजिटल इंडिया के तहत राजस्थान में ई-गवर्नेंस मजबूत हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएँ पहुँच रही हैं। मोबाइल ऐप्स से किसान फसल बेच रहे हैं, और ड्रोन से खेतों की निगरानी हो रही है।

यह संयोजन सबसे सुंदर रूप में पर्यटन में दिखता है। प्राचीन किले अब वर्चुअल रियलिटी से जुड़ गए हैं। जयपुर का हवा महल या आमेर किला पर्यटक ऐप्स पर 360 डिग्री दूर देते हैं। पुष्कर मेला लाइव स्ट्रीमिंग से वैश्विक दर्शकों तक पहुँच रहा है। जैसलमेर के घरों में परंपरागत डिवाइन के साथ सोलर पैनल लगे हैं, जो बीकानेर के एक घर का उदाहरण है जहाँ पुरानी वास्तुकला और आधुनिक तकनीक का संगम है।

हस्तशिल्प को तकनीकी ने नई उड़ान दी है। राजस्थानी ब्लॉक प्रिंट अब ऑनलाइन मार्केट्स

जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बिकता है। डिजाइन सॉफ्टवेयर से आर्टिस्ट्स नए पैटर्न बना रहे हैं। जोधपुर की वुडन क्राफ्ट को 3डी प्रिंटिंग से मजबूती मिल रही है। ई-कॉमर्स ने स्थानीय कारीगरों को वैश्विक बाजार से जोड़ा है। उदाहरणस्वरूप, राजस्थानी साफा और जूतियाँ अब डिजिटल कैटलॉग्स में हैं, जो युवाओं को परंपरा से जोड़ते हैं।

कृषि क्षेत्र में यह मेल चमत्कारिक है। राजस्थान सूखा प्रभावित होने के बावजूद डिजिटल कृषि से बदल रहा है। किसान ऐप्स से मौसम पूर्वानुमान पाते हैं, और ड्रोन से बीज बोया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई बढ़ी है, जो परंपरागत खेती को आधुनिक बनाती है। जैसलमेर के रेगिस्तान में ड्रिप इरिगेशन से सब्जियाँ उग रही हैं। जैविक खेती को प्रमोट करने वाले ऐप्स किसानों को प्रीमियम दाम दिला रहे हैं। यह न केवल उत्पादन बढ़ा रहा है, बल्कि जल संरक्षण भी।

शिक्षा में भी परिवर्तन आया है। ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम हैं, जहाँ बच्चे टेबलेट पर राजस्थानी लोककथाएँ सीख रहे हैं। जयपुर के विश्वविद्यालयों में एआई कोर्सेस राजस्थानी इतिहास पर आधारित हैं।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से युवा कठपुतली कला या लोकनृत्य सीख रहे हैं। यह परंपरा को जीवंत रखते हुए भविष्य की तैयारी करा रहा है। उदाहरण के लिए, भोपा गीतकार अब यूट्यूब पर अपनी प्रस्तुतियाँ अपलोड कर रहे हैं, जो लाखों व्यूज पा रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी ने क्रांति ला दी। टेलीमेडिसिन से दूरदराज के गाँवों में डॉक्टर पहुँच रहे हैं। जोधपुर के एम्स में एआई से डायग्नोसिस हो रहा है। आयुर्वेद को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ प्राचीन जड़ी-बूटियों आधुनिक रिसर्च से सिद्ध हो रही हैं। कोविड काल में राजस्थान ने डिजिटल हेल्थ ऐप्स से लाखों को बचाया।

सांस्कृतिक संरक्षण में डिजिटल अभिलेखागार महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान सरकार ने विरासत को डिजिटाइज किया है। किलों की स्कैनिंग से 3डी मॉडल बने हैं, जो भूंकप जैसी आपदाओं से बचाव करेंगे। लोक संगीत को डिजिटल स्वरूप में संग्रहीत किया जा रहा है। एनजीओ और स्टार्टअप्स मिलकर राजस्थानी बोलियों को ऐप्स में ला रहे हैं। इससे युवा अपनी भाषा नहीं भूलेंगे।

आर्थिक प्रभाव गहरा है। तकनीकी ने रोजगार सृजित किए हैं। आईटी क्षेत्र में हजारों युवा कार्यरत हैं। ई-कॉमर्स से हस्तशिल्प निर्यात बढ़ा है। सौर ऊर्जा से ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर बने हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत राजस्थानी उद्यमी उभर रहे हैं, जो परंपरागत उत्पादों को ब्रांड बना रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, मोम्बत मारजानी जैसी ब्रांड्स बेलेंस गाउन को ग्लोबल बना रही हैं।

चुनौतियाँ भी हैं। डिजिटल डिवाइड ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहाँ इंटरनेट कमजोर है। परंपराओं का व्यावसायिकीकरण उनकी शुद्धता को प्रभावित कर सकता है। युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन सरकार की योजनाएँ जैसे राज-ई-नित्र और डिजिटल गांव इनसे निपट रही हैं।

परंपरा और तकनीकी का यह संगम राजस्थान को सशक्त बना रहा है। यह न केवल आर्थिक विकास ला रहा है, बल्कि सांस्कृतिक निरंतरता भी सुनिश्चित कर रहा है। भविष्य में एआई और वर्चुअल रूरिज्म से राज्य चमकेगा। राजस्थान अब रेत के टीलों से आगे, डिजिटल रेगिस्तान का राजा बन चुका है।

यह प्रक्रिया समावेशी है। महिलाएँ ई-लर्निंग से सशक्त हो रही हैं। आदिवासी समुदाय डिजिटल मार्केटिंग से अपनी कला बेच रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण में स्मार्ट सेंसर रेगिस्तान को हरा बना रहे हैं। राजस्थान का यह नया स्वरूप प्रेरणादायक है।

वर्तमान समय में परंपरा तकनीकी को जोड़े है, और तकनीकी परंपरा के पंखा दोनों मिलकर राजस्थान को विश्व गुरु बना सकते हैं। युवाओं को इस संगम को अपनाना चाहिए। यह नया राजस्थान सिर्फ राज्य नहीं, एक विचार है जहाँ अतीत और भविष्य एक साथ चलते हैं।

–अविनाश जोशी, अतिथि संपादक

वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

संपादकीय

राज्यपाल का अभिभाषण: विकसित राजस्थान की दिशा में सशक्त और सुनियोजित पहल

अभिभाषण में इस बात पर विशेष बल दिया है कि शासन की सफलता का वास्तविक पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में आने वाला सकारात्मक परिवर्तन है



डॉ. अरुण चतुर्वेदी

सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र में राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण राज्य के विकास, सुशासन और जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतिबिंब है। यह अभिभाषण प्रदेश की वर्तमान उपलब्धियों, नीतिगत प्राथमिकताओं और भावी दृष्टि का समग्र, तथ्यपरक और परिणामोन्मुख दस्तावेज है। इसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार सेवा, सुशासन और समावेशी विकास के मूल मंत्र को धरातल पर उतार रही है।

अभिभाषण में लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा को रेखांकित करते हुए इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि

शासन की सफलता का वास्तविक पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में आने वाला सकारात्मक परिवर्तन है। इसी दृष्टि के अनुरूप राज्य सरकार ने विगत दो वर्षों में प्रशासनिक परदर्शिता, जवाबदेही और निर्णयों की गति को सुदृढ़ किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी के माध्यम से सख्त कार्रवाई की गई। परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में पेपर लीक की एक भी घटना सामने नहीं आई। भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं पर कठोर रुख अपनाने हुए 140 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कर 420 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, जिससे युवाओं के मन में विश्वास की पुनर्स्थापना हुई।

युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहा है। इसी संकल्प के साथ अब तक लगभग एक लाख युवाओं को सरकारी नियुक्तियाँ प्रदान की जा चुकी हैं, जबकि 1 लाख 54 हजार 547 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। वर्ष 2026 के लिए एक लाख सरकारी पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया जाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार अवसरों को योजनाबद्ध ढंग से सृजित कर रही है।

खेलों के क्षेत्र में भी राजस्थान ने नई पहचान बनाई है। खेले इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025 का सात शहरों में सफल आयोजन हुआ, जिसमें

देशभर के 222 विश्वविद्यालयों के लगभग 7 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 49 खिलाड़ियों को 2 करोड़ 95 लाख रुपये की सहायता प्रदान कर राज्य ने प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को केंद्र में रखते हुए व्यापक सुधार किए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 2 लाख 37 हजार से अधिक विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिलाया गया, जिसके लिए लगभग 996 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई। वहीं, सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत 66 लाख से अधिक विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग उपलब्ध कराने हेतु 482 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई।

विगत दो वर्षों में 185 नए महाविद्यालय भवनों का लोकार्पण, 71 नए महाविद्यालयों की स्थापना और 17 महाविद्यालयों का स्नातकोत्तर स्तर पर उन्नयन किया जाना राज्य की उच्च शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तकनीकी शिक्षा को भविष्य की आवश्यकताओं से जोड़ते हुए 21 नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रारंभ किए गए तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग नीति लागू कर राजस्थान को तकनीकी नवाचार के अग्रणी राज्यों

की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए सरकार ने वित्तीय, संरचनात्मक और तकनीकी सहयोग को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 71 लाख 79 हजार किसानों को लगभग 718 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। समर्थन मूल्य पर 21 लाख 37 हजार मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद कर किसानों को 320 करोड़ रुपये का बोनस दिया गया। इसके साथ ही, अल्पकालीन व्याज मुक्त फसली ऋण के रूप में 78 लाख से अधिक लाभार्थियों को 44 हजार 355 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जिससे किसानों की तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति के साथ उनकी आय में स्थायित्व आया है।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार की पहलें प्रभावी सिद्ध हो रही हैं। 15 लाख 95 हजार महिलाओं को 'लक्षपति दीदी' श्रेणी में लाकर उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया गया है। सामाजिक सुरक्षा पंथान योजनाओं के अंतर्गत 91 लाख 73 हजार लाभार्थियों को 12 हजार 700 करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित किया गया। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 103 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए

हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राज्य की पहचान बनकर उभरी है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ 36 लाख परिवारों को 25 लाख रुपये तक का कैंसलेंस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। विगत दो वर्षों में लगभग 37 लाख रोगियों को 7 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक का निःशुल्क उपचार प्रदान किया गया। राजस्थान ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। फरवरी 2025 में 19 हजार 165 मेगावाट की अधिकतम बिजली मांग बिना कटौती के पूरी की गई, वहीं किसानों को 46 हजार 500 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाया गया है।

समग्र रूप से अभिभाषण इस तथ्य को रेखांकित करता है कि राजस्थान सरकार ने विकास को ठोस क्रियान्वयन, मापनीय परिणामों और जन विश्वास से जोड़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश विकसित भारत-विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। सुशासन, समावेशी विकास और दीर्घकालिक ओदृष्टि के साथ राजस्थान आज एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की ठोस आधारशिला बल चुका है।

–डॉ. अरुण चतुर्वेदी, अध्यक्ष, राजस्थान वित्त आयोग

ऐसे तो “विकसित भारत” नहीं बनेगा

विकसित भारत यदि केवल बातों और नारों से हो जाता तो शायद भारत कभी का विकसित हो चुका होता



राजेन्द्र भाणावत

जब से प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और 'विकसित भारत' बनाने की बात कही है, सत्ता धारी दल के सभी नेताओं के भाषणों एवं सरकार की सभी योजनाओं में 'विकसित भारत' शब्द सम्मिलित हो गया है। इसका सबसे ताजा उदाहरण तो हाल ही में घोषित "विकसित भारत-जी राम पी" योजना है, जिसे नरेंगा के स्थान पर लाया गया है।

विकसित भारत यदि केवल बातों और नारों से हो जाता तो शायद भारत कभी का विकसित हो चुका होता। इसी प्रकार का एक नारा 'गरीबी हटाओ' तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, किंतु गरीबी आज भी ज्यों की त्यों है तथा गरीब और अमीर के बीच खाई तो पहले से भी कहीं अधिक चौड़ी हो गई है।

सरकार के प्रयास भी भारत को विकसित बनाने की ओर दिखाई नहीं देते। यदि यही स्थिति रही तो यह सपना केवल सपना ही बनकर रह जाएगा और कभी साकार होकर धरातल पर नहीं उठेगा। हम वर्तमान में किस प्रकार की प्राथमिकताएँ तय कर रहे हैं और किस प्रकार की दिशा में जा रहे हैं, उसके लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा।

इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर कई बार घोषित किया जा चुका है। इसी इंदौर शहर में सीवर का दूषित पानी पीने से 27 लोगों की मौत हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र के निवासी लगभग आठ महीने से स्थानीय प्रशासन और जन प्रतिनिधियों को गंदा पानी आने की शिकायत कर रहे थे किंतु किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप

इसी मलमूत्र युक्त पानी को नागरिक पीते रहे और सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार हो कर अस्पतालों के आई सी यू में पहुँच गए। जब मामला मीडिया में बहुत चर्चित हुआ तब जाकर प्रशासन की आँख खुली और इस दिशा में कुछ कार्रवाई की गई। जो शहर लगभग देश में सबसे स्वच्छ शहर का इनाम प्राप्त कर रहा हो, वहाँ के मासूम नागरिकों को यदि गंदा पानी पीने के कारण काल कबलित होना पड़े तो यह विकसित भारत की दिशा में बढ़ता कदम तो कतई नहीं कहा जा सकता।

उत्तर प्रदेश के नोएडा में हाल ही में एक कार ऐसे खड़े में गिर गई जहाँ 35 फीट पानी भरा हुआ था। यह खड्डा किसी भवन के बेसमेंट के निर्माण के लिए बनाया गया था और लगभग दो वर्षों से इस स्थिति में था। कोहरे के कारण दिखाई कम दे रहा था और कार चालक इस पानी में चला गया। यह 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युराजग मेहता था जिसने हिममत रखकर डूबने से पहले कार के ऊपर खड़े होकर दो घंटे तक मोबाइल की रोशनी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। उसने अपने पिता को अपनी लोकेशन भेज दी जिन्होंने फोन नंबर 112 पर सूचित भी कर दिया। जिला प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आरएफ के सैकड़ों लोगों के आने के बावजूद किसी ने उसे बचाने का प्रयास तक नहीं किया और मृक दर्शक बने रहे।

इसका कोई उत्तर प्रशासन के पास नहीं है कि केवल 15-20 किलोमीटर दूर हिंडन एयर बेस पर उपलब्ध हेलीकॉप्टर की मदद से उस युवक को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? जब किसी डूबते हुए युवक को आधुनिकतम तकनीक के सहारे सुशासन देने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 घंटे तक नहीं बचाया जा सकता, तो विकसित भारत की बात करना बेमानी होगा। यही वह राज्य है जहाँ नोएडा के पास जेवर में विश्व स्तरीय हवाई अड्डा बनने की बात हो रही है। सरकार ने शायद यह समझ लिया है कि विश्वस्तरीय एयरपोर्ट बनाने, बुलेट ट्रेन चलाने से, आधुनिकतम भवन

बनाने से, महंगी गाड़ियों में चलने से या बड़े-बड़े स्टेडियम बना देने से भारत विकसित हो जाएगा। सरकार को यह समझना होगा कि भारत विकसित तब होगा जब लोगों की शुद्ध वायु और पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा और योग्यता अनुसार रोजगार उपलब्ध हो।

जहाँ तक वायु प्रदूषण का सवाल है, स्थिति इतनी खराब है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी नेसल स्टिप लगाकर बाहर निकल रहे हैं, ताकि कहीं बीमार ना पड़ जाएँ। जिस देश की राजधानी का ए क्यू आई 800 तक हो जाए, वह देश कैसे विकसित कहला सकता है। निवेश लाने के लिए सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है और निवेशकों को लुभाने के लिए करोड़ों, अरबों रुपए खर्च भी करती है, किंतु यह भूल जाती है की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कोई भी विदेशी निवेशक यहाँ आकर निवेश करना उचित नहीं समझेगा। बाहर के लोग जब आकर आकर सांस तक न ले पाएँ, पीने का साफ पानी तक ठीक से न मिल पाए, तो वहाँ आयेगी ही क्यों?

भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक रह चुकी हैं और वर्तमान में हार्वर्ड में प्रोफेसर हैं, ने दावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकनोमिक फोरम में बातचीत करते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में निवेश तब ही आएगा जब भारत सरकार प्रदूषण की गंभीर स्थिति के संबंध में प्रभावी कार्रवाई करे।

गीता गोपीनाथ ने हॉर्नब्यू टुडे ग्रुप की मालकिन कली पूरी से यह बात कही जब उनसे भारत में अच्छे होते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंध में पूछा गया। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.8 लाख लोग केवल प्रदूषण के कारण परते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। उनके अनुसार "इज ऑफ डूइंग बिजनेस" का कोई अर्थ नहीं है यदि देश में शुद्ध वायु तक उपलब्ध नहीं है। आप कितने ही लाल कालीन विदेशियों के लिए भारत आने पर क्यों न बिछा दें, हवा में इतनी गंदगी है कि कोई भी व्यक्ति भारत आने से पहले 10 बार सोचेगा। जो बातें भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ

ने कही हैं उनको सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और उन पर रक्षायक रूप अपनाने के बजाय उस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। समय आ गया है जब नेता गुणों को केवल अपने और अपने परिवार की सुख सुविधा पर ध्यान देने की बजाय उन्हें साधारण जनता की सुविधा को बेहतर करने और उनके जीवन को सरल बनाने की दिशा में प्रयास करने होंगे। यदि यहाँ के जन प्रतिनिधि और अधिकारी गुण स्वयं को जनता का मालिक मानते रहे तो कभी भी देश न तो आत्मनिर्भर हो पाएगा और ना ही वह विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो पाएगा। अतः यदि भारत विकसित होना है कि देश में प्रगति हो, औद्योगीकरण बढ़े और बाहर से निवेश आए तो उसे पहले वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। भारतीय मूल की एक प्रख्यात प्रोफेसर का दावोस में विदेशी समुदाय के समक्ष इस प्रकार की बात करना भारत सरकार को आईना दिखाने के समान है।

नगरीय प्रशासन व्यवस्था लगभग ठप्प है। महानगरों में रहने वाली आबादी का लगभग 40 प्रतिशत नगरीय जीवन जी रहा है।

दिल्ली में संसद भवन से केवल 40-50 किलोमीटर दूर किराड़ी जैसी अनेक बस्तियाँ हैं जहाँ लोगों को प्रतिदिन एक फुट सीवर के पानी के क्रीचरों में पाँव रखकर अपने घरों में जाना पड़ता है। इस क्षेत्र के वीडियो सोशल मीडिया में प्रतिदिन देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर स्वयं को भारतीय कहने पर शर्म आने लगती है। विकसित होने की बात करने से पहले हमें यहाँ के नागरिकों को कम से कम मनुष्य के लिए जीने लायक व्यवस्था तो उपलब्ध करानी होगी।

सरकार भले ही सोमनाथ में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ मनाने में लोगों को लगा दे, किंतु इससे लोगों का जीवन बेहतर नहीं होगा। आप किसी भी शहर में चले जाएँ, कूड़े के ढेर, गंदे पानी से अटी सड़कें, जर्जर स्कूल और बिना चिकित्सक के अस्पताल मिल जाएंगे। रोजगार का हाल यह है कि स्नातक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोग भी

डिलीवरी बाँयज़ की तरह काम करने के लिए मजबूर हैं।

विकसित भारत का नमूना हाल ही में हमें देखने को मिला जब प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात के प्रमुख शहर सूरत में 21 करोड़ की लागत से बनी नई पानी की टंकी, जिसकी क्षमता 11 लाख लीटर की थी, 9 लाख लीटर के पानी का वजन भी नहीं सह सकी और पहली बार में ही ढह कर जमीन पर गिर गई। क्या इस पर व्यय हुए 21 करोड़ किसी अधिकारी से सचल होंगे?

विकसित भारत तभी बनेगा जब लोगों को धर्म, जाति के प्रपंचों में उलझाए रखने और उन्हें तथाकथित इतिहास की गौरव गाथा का गुणगान करने में व्यस्त रखने के बजाय उनकी वर्तमान ज्वलंत समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए। शिक्षित और वैज्ञानिक सोच वाले समाज के अभाव में विकसित भारत की कल्पना करना संभव नहीं है। सरकार ने विकास का अर्थ उत्कृष्टता के टापू बनाना ही मान लिया है। यह विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ कदम नहीं कहा जा सकता।

जहाँ शहरों के फुटपाथ अनुपयोगी वाहनों से भरे पड़े हों, सड़कों पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना जैसे लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार हो, वह भारत विकसित कैसे बनेगा? जहाँ अंधविश्वास, लोगों को कदम कदम पर परोसा जाता हो, बाबाओं को 'जेड' श्रेणी की सुखदा दी जाती हो और आम जनता को वाहनों के नीचे कुचले जाने के लिए छोड़ दिया जाता हो, उसे हम विकसित भारत कैसे कहेंगे?

अशिक्षित, बीमार, बेरोजगार और असुरक्षित नागरिकों के भारत को कभी भी विकसित भारत नहीं कहा जाएगा, न ही उस भारत को विकसित कहा जाएगा, जहाँ शुद्ध पेयजल उपलब्ध न हो, शहरों में गंदगी के ढेर लगे हों और जहाँ कानून का राज नहीं हो। विकसित भारत बनाने के लिए सरकार को अपनी प्राथमिकताओं का उपरोक्तानुसार पुनर्निर्धारण करना होगा ताकि सही दिशा में तेजी से अग्रसर हो सके।

–राजेन्द्र भाणावत, (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



पंडित अनिल शर्मा

मिथुन, मंगल-मकर, बुध-मकर, गुरु-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-कुम्भ, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज सर्वाथि सिद्ध योग रात्रि 3:27 से सूर्योदय तक है। रवियोग रात्रि 3:27 से आरम्भ होगा। आज प्रदोष व्रत, वैधुति पुण्य, कल्पादि है। श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:38 तक, लाभ-अमृत 8:38 से 11:19 तक, शुभ 12:40 से 2:01 तक, चर 4:42 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:18, सूर्यास्त 6:03

राशिफल

शुक्रवार 30 जनवरी, 2026

माघ मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2082, आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 3:27 तक, वैधुति योग रात्रि 4:58 तक, बालव कर्ण दिन 11:10 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा। गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-मकर, बुध-मकर, गुरु-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-कुम्भ, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

3:27 से आरम्भ होगा। आज प्रदोष व्रत, वैधुति पुण्य, कल्पादि है। श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:38 तक, लाभ-अमृत 8:38 से 11:19 तक, शुभ 12:40 से 2:01 तक, चर 4:42 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:18, सूर्यास्त 6:03



मेघ

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति से संपर्क बन सकता है। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।



तुला

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक के कारण कार्य में विलम्ब होने का भय है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।



वृष

आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी।



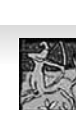
वृश्चिक

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने का भय है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।



मिथुन

नवीन कार्य के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक अडचन दूर होने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



धनु

परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। अपसी सहयोग-समन्वय से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।



सार-समाचार

हज यात्रियों की ट्रेनिंग एवं टीकाकरण 8 फरवरी को रजा गार्डन में

उदयपुर,(का.सं.)। हज कमेटी ऑफ राजस्थान के निर्देशानुसार उदयपुर जिला एवं राजसमंद जिला से वर्ष 2०26 में हज पर जाने वाले हज यात्रियों की ट्रेनिंग व टीकाकरण 8 फरवरी को अलीपुरा रजा गार्डन में आयोजित होगा। जिला हज कमेटी ट्रेनर मो. अयुब डायर के अनुसार निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार 8 फरवरी को अलीपुरा मस्जिद कमेटी द्वारा हाजियों को हज के दौरान करने वाले अरकान की जानकारी इस्लामिक विद्वानों द्वारा सुबह 9 बजे से 4 बजे तक दी जाएगी। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के तत्वाधान मे उदयपुर जिला चिकित्सा अधिकारी व उदयपुर हज कमेटी हज पर जाने वाले उदयपुर के 177 एवं राजसमन्द के हाजियों का टीकाकरण कर मेडिकल प्रमाण पत्र दिया जायेगा। ट्रेनिंग के दौरान इस वर्ष हज पर जाने वाले यात्रियों को हज कमेटी ऑफ इंडिया अल्पसंख्यक मामालता भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की भी जानकारी भी दी जाएगी। हज यात्रा पर हाजियों के साथ विदेशी मुद्रा ले जाने की व्यवस्था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई जिसके लिए चेतक सर्किल ब्रांच और पटेल सर्किल ब्रांच पर संपर्क कर सकते है। एक हाजी द्वारा हज यात्रा पर कम से कम 5०0 सऊदी रियाल ले जाना अनिवार्य होगा। इस वर्ष हज यात्रियों का मेडिकल फिटनेस भी किया जायेगा।

महिला की मौत पर परिजनों-समाजजनों का कलेक्ट्री पर प्रदर्शन

उदयपुर, (निसं)। उदयपुर के सरकारी पन्नाधाय महिला हॉस्पिटल में दिलीवरी के बाद महिला की मौत मामले में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विप्र महासेना की ओर से गुरुवार को प्रदर्शन किया गया। लोगों ने बताया कि महिला मीना जोशी ने 13 जनवरी को सिंजेरियन मे बच्ची को जन्म दिया था। उसके बाद से महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई। विप्र महासेना के राष्ट्रीय संरक्षक डॉ हेमंत जोशी ने बताया कि परिजन बार-बार उसकी हालत के बारे में डॉक्टरों को बताते रहे। फिर दूसरे दिन प्रसूता का वापस एक आपरेशन किया। जिसके कुछ समय बाद डॉक्टरों ने बताया कि प्रसूता की दोनों किडनी खराब हो गई। जबकि वह प्रसव से पहले वह स्वस्थ थी। ऐसे में परिजन प्रसूता को अहमदाबाद लेकर गए। जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने आपरेशन और दवाइयों में लापरवाही को लेकर आरोप लगाया है। इसे लेकर परिजनों और क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर नमित मेहता को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई।

अमृता हाट एवं हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ आज से
प्रतापगढ़, (निसं)। महिला स्वयं सहायता समूहों के विभिन्न उत्पादों के विपणन एवं महिलाओं के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए समर्पित करने हेतु जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता विभाग एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा दिनांक 3०.०1.2०26 से ०3.०2.2०26 तक अमृता हाट एवं हस्तशिल्प मेला का आयोजन मोहल्लाल सुखाड़िया स्टेडियम में किया जा रहा है। महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक नेहा माथुर ने बताया कि अमृता हाट मेले का शुभारंभ 30 जनवरी, शुक्रवार को प्रातः 11 बजे मोहल्लाल सुखाड़िया स्टेडियम में होगा। मेला प्रतिदिन प्रातः 1० बजे से रात्रि 1० बजे तक चलेगा व मेले का समापन समारोह 3 फरवरी को सांय 4 बजे से होगा।

राज्य भर में पीएमश्री चयनित राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी एंड लाइन आकलन

उदयपुर, (निसं)। पीएमश्री चयनित राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के सीखने की गति एवं अधिगम परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से अधिगम संवर्धन कार्यक्रम अंतर्गत कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की गयी है। इन विद्यालयों में संचालित उपचारात्मक शिक्षण के परिणामों का आंकलन करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा बेसलाइन एवं एन्डलाइन टूल का निर्माण कर उनके निर्देशन में राज्य में संचालित चयनित 628 पीएम श्री विद्यालयों की कक्षा 6, 8, 1० एवं 12 के तीन संकायों में चयनित विद्यार्थियों का डाइट के माध्यम से एन्डलाइन आकलन 29 जनवरी को सम्पन्न हुआ। पूर्व में बेसलाइन आंकलन 21 अप्रैल 2025 को हुआ था। आर एस सी ई आर टी द्वारा बेसलाइन एवं एंड लाइन आकलन के आंकड़ों का विश्लेषण कर उपचारात्मक शिक्षण की उपाययता एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशीलता को ज्ञात किया जाएगा व जारी रिपोर्ट अनुसार जिले की स्थिति अनुसार कार्ययोजना बनाकर आवश्यक कार्य किये जावेंगे। यह राज्य स्तरीय एन्डलाइन आकलन श्रेता फगीरिया, निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के निर्देशन में प्रोफेसर बीना नाहर, एसोसिएट प्रो. कपिला कंठालिया एवं टीम द्वारा किया गया।

उमराह यात्रा से लौटे हज खिदमत कमेटी के पदाधिकारियों का किया इस्तकबाल

निम्बाहेड़ा,(निसं)। 20 दिवसीय उमराह यात्रा से लौटे हज खिदमत कमेटी निम्बाहेड़ा के पदाधिकारियों का इस्तकबाल प्रोग्राम मंगलवार की शाम उदयपुर रोड स्थित एक फार्म हाउस पर कॉन्ट्रेक्टर एवं समाजसेवी मोहसिन खान व मदर्स डायनोस्टिक एण्ड डिजिटल एक्सरे के ऑनर शकील अहमद द्वारा आयोजित किया गया। जिसमें हज कमेटी के पदाधिकारियों ने शिरकत की। प्रोग्राम में हज खिदमत कमेटी के सदर मतलबुल अजमेरी, सचिव हाजी अख्तर पटेल, अंजुमन नायब सदर हाजी ख्वाजा हुसैन, एडवोकेट अब्दुल कलाम का साफा बांधकर एवं गुलपरीशी कर इस्तकबाल किया और मुंह मीठा कराकर उमराह की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कॉन्ट्रेक्टर खान एवं मदर्स लैब के अहमद द्वारा मेहमानों के लिए दावत का प्रोग्राम भी रखा गया। इस मौके पर हाजी भूरू जागीरदार, अब्दुल सलाम, अनोस अहमद, डॉ. इमरान खान, मोहम्मद फारुक छिपा, भाया बैट्टी, पत्रकार मोईन खान आदि मौजूद रहे।

आमजन तक पहुंचाएंगे वीबी-जी-राम-जी अधिनियम की जानकारी

बांसवाड़ा,(निसं)। विकसित भारत-जी राम-जी अधिनियम के प्रचार-प्रसार के लिए 8 मार्च तक जन संवाद और आईईसी की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अधिनियम के कानूनी प्रावधानों और फायदों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा सघन जन संवाद आधारित सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके लिए छह सप्ताह का कलेण्डर निर्धारित किया गया है। इसके तहत वीबी-जी राम जी अधिनियम की वैधानिक विशेषताओं पर सार्वजनिक स्पष्टता सुनिश्चित की जाएगी। दूसरे सप्ताह के तहत 2 से 8 फरवरी तक अधिकार संरक्षण संकल्प दिवस मनाए जाएंगे। इस दौरान ग्राम स्तर पर सामूहिक शपथ पाठ तथा बैनर पोस्टर के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों को प्रचारित किया जाएगा। विकसित भारत ग्राम संवाद के तहत तीसरे सप्ताह 9 से 15 फरवरी तक चौपाल, ग्राम सभाओं और ग्राम स्तरीय बैठको का आयोजन तथा दीवार लेखन एवं फलेक्स बैनर के माध्यम से ग्राम स्तर पर अधिनियम की बुनियादी समझ बनाने तथा अधिकारों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी। इसी क्रम में 16 से 22 फरवरी तक चौथे सप्ताह के दौरान अहिंसा से अधिकार थीम पर आधारित गतिविधियां होंगी। इनमे विद्यालयों मे पेंटिंग, भाषण एवं अन्य प्रतियोगिताएं, बच्चों की पेंटिंग का प्रदर्शन, रोजगार अधिकार जागरूकता यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। पांचवें सप्ताह में 23 फरवरी से 1 मार्च तक नए अधिनियम की बात, पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ के तहत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ संवाद होगा।

ग्रामीण अंचल में हुआ नेत्रदान, दो व्यक्तियों को मिलेगी रोशनी

निम्बाहेड़ा (निसं)। लांसस क्लब निम्बाहेड़ा गोलंड ग्रामीण अंचल निम्बाहेड़ा से 7० किलोमीटर दूर गांव धमतार जिला प्रतापगढ़ में दिवंगत नंदलाल जैन (मोदी) की मृत्युपरिणत पुत्र योगेश जैन (मोदी) द्वारा इस दुखद घड़ी में राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत लांसस क्लब निम्बाहेड़ा गोलंड द्वारा नेत्रदान का पुनीत एवं साहसिक कार्य कारवाया गया। क्लब के आई डोनेशन चेयरमैन डॉ. आर.आर. बिजोई ने बताया कि यह इस सत्र का 11वां एवं क्लब द्वारा करवाया गया कुल 24वाँ नेत्रदान है।

बीएन विवि की मेजबानी में वेस्ट जोन बास्केटबॉल प्रतियोगिता 3 फरवरी से

उदयपुर (निसं)। भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय की मेजबानी में पहली बार हो रहे वृहत स्तर पर आगामी 3–6 फरवरी तक आयोजित वेस्ट जोन बास्केटबॉल प्रतियोगिता को लेकर गुरुवार को विश्वविद्यालय के सभागार में चेयरपर्सन प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत की अध्यक्षता में तैयारी हेतु बैठक का आयोजन हुआ।

प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत ने बताया कि आयोजित प्रतियोगिता में राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गोवा के 127 विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के 15०० से अधिकखिलाड़ी एवं कोच भाग लेंगे। शनिवार से खिलाड़ियों का आमनन होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए विभिन्न कमेटियों का गठन कर दायित्व सौंपा गया है।

रजिस्ट्रार डॉ.एन.एन.सिंह राठौड़ ने बताया कि मैच का शुभारंभ 3 फरवरी



उदयपुर में बीएन विवि की मेजबानी में आयोजित होने वाली वेस्ट जोन बास्केटबॉल प्रतियोगिता को लेकर तैयारी बैठक का आयोजन किया गया।

को प्रातः 1० बजे संस्थान के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर होगा। प्रतियोगिता से पूर्व पांचों राज्यों से आये खिलाड़ियों की ओर से मार्च पास्ट किया जायेगा। इस प्रतियोगिता में अधिक टीमों के भाग लेने पर बीएन विश्वविद्यालय के इंडोर

एवं आउटडोर खेल मैदान के अतिरिक्त शहर के अन्य मैदान जिसमें फतेह सीनियर विद्यालय एवं एमबी कॉलेज के अटल बिहारी वाजपेयी इन्डोर में व्यवस्था की गयी है, जिसमें दर रात मैच तक प्रतियोगिता का संचालन की

- 127 विश्वविद्यालय के 1500 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग, तैयारी बैठक का हुआ आयोजन

व्यवस्था रहेगी। 2 फरवरी को मैच रेफरी एवं कोच की बैठक रहेगी जिसमें आयोजित प्रतियोगिता के नियमों से अवगत कराया जायेगा एवं प्रतियोगिता का अंतिम प्रारूप तैयार होगा। बैठक में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय समिति के चेयरमेन करणसिंह चुण्डावत, विश्वविद्यालय के प्रेसीडेन्ट प्रो. चेतनसिंह चैहान,विवि स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमेन डॉ. अभिमन्यु सिंह राठौड़,सचिव डॉ. हितेश रावल, प्रो. रेणु राठौड़, डॉ. राजेन्द्र सिंह शक्तावत, डॉ.भूपेन्द्र सिंह चैहान, डॉ. रजनी अरोड़ा, डॉ. जयसिंह बागोला सहित विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता एवं निदेशक उपस्थित थे।

जिला कलेक्टर मेहता रहे ऋषभदेव उपखंड दौरे पर

उदयपुर, (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुशासन के संकल्प को साकार करने की दिशा में जिला कलेक्टर नमित मेहता जिले के ग्रामीण अंचलों के नियमित रूप से दौरे कर रहे है। इसी ऋम में कलेक्टर मेहता गुरुवार को ऋषभदेव उपखंड के दौरे पर रहे।

- उपखंड स्तरीय कार्यालयों का किया वार्षिक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश



ऋषभदेव उपखण्ड कार्यालय का निरीक्षण करते जिला कलेक्टर मेहता।

समीक्षा की।

कलेक्टर मेहता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर आमजन से जुड़े परिवादों का निस्तारण पूरी संवेदनशीलता और समयबद्ध तरीके से किया जाए।

उन्होंने कार्यालय परिसरों में पुरानी पत्रावलियों व फाइलों को सुव्यवस्थित

रूप से संघारित करने तथा रिकॉर्ड प्रबंधन को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। निरीक्षण के दौरान ऋषभदेव उपखंड अधिकारी रामकरण सिंह, तहसीलदार आशीष सोनी, विकास अधिकारी पंकज कुमार आर्य सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रतापगढ़ को कुछ रोग मुक्त बनाने का चलेगा अभियान

- 30 जनवरी से 13 फरवरी होंगे विविध कार्यक्रम

के द्वारा गाँव-गाँव घर-घर दस्तक देकर स्वास्थ्य कर्मों द्वारा कुछ रोग की जांच की जाएगी। जिससे शीघ्र कुछ रोगी की पहचान कर उनका उपचार प्रारंभ किया जा सके। सीएमएचओ डॉ जीवराज मीणा ने बताया कि जिले को कुछ मुक्त करने के लिये हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

स्पर्श कुछ जागरूकता अभियान के तहत कुछ प्रभावित व्यक्तियों के साथ भेदभाव को समाप्त करने और उन्हे

मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। अभियान अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता शिक्षा विभाग आदि के समन्वय से ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर जागरूकता संदेश दिया जायेगा उन्होंने बताया कि कुछ माइकों बैकटीरियम लेप्री से होने वाला रोग है। यह अनुवांशिक रोग नहीं है।

यह पहले से पापों एवं बुराइयों के कारण नहीं होता है। कुछ के मुख्य लक्षण त्वचा के रंग में बदलाव तथा संवेदना में कमी आना है।

संपूर्णता अभियान 2.0 की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक

बांसवाड़ा,(निसं)। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा देश के आकांक्षी ब्लॉकों में विकास की गति तेज करने के लिए संचालित संपूर्णता अभियान 2.० के क्रियान्वयन के लिए सज्जनगढ़ ब्लॉक के अधिकारियों की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में अभियान के प्रभावी संचालन और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर चर्चा

की गई। पोषण, शिक्षा एवं एफएमडी टीकाकरण पर मुख्य फोकस रहेगा। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सज्जनगढ़ ब्लॉक में पोषण, शिक्षा एवं पशुपालन से जुड़े मानकों पर शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर डॉ. यादव ने बताया कि अभियान का शुभारंभ 2 फरवरी को होगा जो 14 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान मुख्य रूप से 6 संकेतकों पर कार्य किया जाएगा

जिसके तहत पोषण विभाग पूरक पोषण के प्रति जागरूकता लाने, पशुपालन विभाग खुरपका-मुंहपका रोग वैक्सिनेशन के प्रति पशुपालकों को जागरूक करने, शिक्षा विभाग स्कूलों में स्वच्छता के लिए व्यापक जागरूकता लाने का कार्य करेगा। बैठक में मुख्य आयोजना अधिकारी सत्येंद्र कुमार शाह ने नीति आयोग के निर्देशों के अनुसार अभियान के कैलेंडर की जानकारी साझा दी।

वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में देश-विदेश के कलाकार देगें प्रस्तुतियां

उदयपुर, (निसं)। वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 'म्यूजिक विदाउट बॉर्डर्स' के दस वर्ष पूरे कर फरवरी माह में एक बार फिर से जिक सिटी उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान कर रहा है। हिंदुस्तान जिक के सहयोग से सेहर, राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित होने वाला यह फेस्टिवल 6 से 8 फरवरी तक होगा, जो दर्शकों का संगीत और संस्कृति अभूतपूर्व उत्सव में सम्मिलित होने का मौका देगा।

भारत में विश्व संगीत को महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के एक दशक का उत्सव मनाते हुए, इस वर्ष भारतीय संगीत के सबसे प्रतिष्ठित के साथ 1० से अधिक देश के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार शामिल हैं। तीन दिवसीय उत्सव में 2०+ बैंड और कलाकार शामिल होंगे, जो लोक और स्वदेशी परंपराओं से लेकर समकालीन, पॉप और ग्लोबल फ्यूजन तक की शैलियों की प्रस्तुति से दर्शकों को विशेष संगीत और संस्कृति से रूबरू कराएंगे। फेस्टिवल में जाने-मानी भारतीय कलाकार कैलाश खैर भक्ति भावनाओं से भरे लोकगीत और सूफी संगीत पेश करेंगे, वहीं अमित त्रिवेदी एक अलग ही तरह की एनर्जी वाले लाइव अनुभव देने के लिए तैयार हैं जो परंपराओं का आज के संगीत से जोड़ता है। इसमें और भी रंग भरेंगे जोनिता गांधी, जिनकी ग्लोबल

बढ़ाते हुए, वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2०26 में एक रोमांचक इंटरनेशनल प्रस्तुति होगी जिसमें कई कलाकार पहली बार भारत में परफॉर्म करेंगे। सेलीन सुबुलट्रे (तुर्की) और कैले माम्बो (स्वीडन) जो मॉडर्न बीट्स के साथ रिच और जोशीले लैटिन रिदम लाएंगे, वेलैरी एक्रोमे (केमरून) एफ्रो-पॉप और एफ्रो-रॉक सहित यह फेस्टिवल दर्शकों को विश्व संगीत से परिचित कराएगा। इंटरनेशनल कलाकार अल्जीविया की मशहूर आवाज कोफियान सैदी, लुसिबेला (केप वर्ड), 9 ग्रेडर नॉर्ड (नॉर्वे), बोलेसी (पोलैंड), और फ्लेमैको डीम (स्पेन) शामिल हैं, जो एक अनोखी पिता-पुत्र की जोड़ी है जिनके परफॉर्मेंस पीढ़ियों तक म्यूजिकल विरासत के आगे बढ़ा रहे हैं। फेस्टिवल की ग्लोबल पहचान को

सड़क हादसे में बालक की मौत, मांगों को लेकर प्रदर्शन

उदयपुर,(निसं)। स्कूल से लौटते समय साईकिल से गिरने पर मिनी ट्रक के कूचलने से बालक की मौत पर गुरुवार को आक्रोषित लोगों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रास्ता जाम किया। जहां प्रशासन से बातचीत होने के बाद मामला शांत हुआ।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार सांय चितोड़गढ़ हॉल प्रतापनगर थाना क्षेत्र आशापुरा नगर निवासी गौरांग शर्मा (11) हमेशा की तरह साईकिल पर स्कूल से घर लौट रहा था। जहां बीच रास्ते हाड़वे पर नाकोड़ा नगर रकमपुरा जाने वाले रोड़ पर सड़क पर गड़्डे में साईकिल जाने से संतुलन बिगड़ने पर वह नीचे गिर पड़ा। इसी दौरान आए मीनी ट्रक ने उसे कूचल दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।

हादसे को देख चालक ट्रक छोड़ कर मौके से फरार हो गया। इधर स्कूना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मृतक को एमबी चिकित्सालय मोचंरी में रखवाया। घटना के दूसरे दिन गुरुवार को

आक्रोषित लोगों ने मृतक के परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर घटना के लिए जिम्मेदार के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसकी सूचना मिलने पर प्रतापनगर थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह ने मौके पर पहुंच कर समझाईश कर प्रतिनिधी मंडल को बातचीत कराने के लिए अपने साथ उच्चाधिकारियों के पास ले गए। जहां संबंधित अधिकारी से शिकायत का आश्वासन मिलने पर मामला शांत हुआ।

 प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
 राजस्थान सर्वजनिक प्रचायत अधिनियम 1९५९
 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
 कार्यालय महापक आरुफ देवशान विभाग , ऋषभदेव
 समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
 पुष्टकान्वय:DEV/RISHABDEV/RTST/2026/140
 शुद्धि प्राप्त की SOMA LAL PATEL, पु-चेटर, कोचबाबा तहसील ऋषभदेव उदयपुर राजस्थान 313802 ने राजस्थान सर्वजनिक प्रचायत अधिनियम 1९५९ की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रचायत ग्राम जन प्रचका एवं विकास संस्थान भूपर ऋषभदेवJARIOM SEVA SAMITI RATANPURA POST. BHUDDHARTAHASIL RISHABDEVDIST. UDAIPUR RAJASTHAN 313802 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रियाहै।
 आरम्भ धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त प्रचायत, जिसकी जांच की जा रही है, में गिर रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जात है कि ये इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिनों के भीतर उक्त प्रचायत के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करेंगे और यह पटुति किया जात है कि यदि उपरोक्त निधि अधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निरस्त रीति से निरस्त किया जायेगा।
 आज दिनांक 28.०1.2०26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
 आहवा तारीख पेसी 02/०4/2०26
 सहायक आयुक्त
 देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

क्रमांक : न्पा.फ.सं. / निर्माण / 2०25-26 / ई- 1२ / 726	दिनांक :- 21.०1.2026
ई निविदा सूचना संख्या – ई-12/2025-26	
नगरपालिका फतहनगर सनवाड द्वारा राजस्थान सरकार के समुचित वर्ग के सूचीबद्ध ठेकेदारों / संवेदकों एवं केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के विभिन्न उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो उनसे निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई- प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण इंटर्नेट साईट www.eproc.rajjasthan.gov.in , www.sppp.rajjasthan.gov.in पर उपलब्ध है।	
कुल निविदा के कार्य	कुल ०6 कार्य
निविदा की अनुमानित लागत	राशि रु0 131.76 लाख
युगोप नं.	DLB2526WSOB32067, DLB2526WSOB32068, DLB2526WSOB32069, DLB2526WSOB32070, DLB2526WSOB32071, DLB2526WSOB32072
राज.संवाद / सी / 25 / 18730	अधिशामी अधिकारी

कार्यालय ग्राम पंचायत सरे, पंचायत समिति बडगाँव, जिला-उदयपुर (राज.)
क्रमांक: ग्रापस/2०25-26/134 दिनांक: 28.०1.2०26
-: ई निविदा सूचना वर्ष 2०25-26 :-
ग्राम पंचायत सरे में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु इच्छुक एवं सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ई निविदा द्वारा निविदाएं दिनांक 3.2.26 6:०0 पीएम तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/जानकारी [sppp. rajasthan.gov.in](http://sppp.rajjasthan.gov.in) एवं eprocrajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN No ZUD2526WSOB04259

प्रशासक

ग्राम पंचायत-सरे

पं.स. बड़गांव, जिला-उदयपुर

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत-सरे

पं.स. बड़गांव, जिला-उदयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत सरे, पंचायत समिति बडगाँव, जिला उदयपुर
क्रमांक: दिनांक :-
खुली बोली निविदा सूचना
ग्राम पंचायत सरे के अधीनस्थ ग्रामों में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक निविदादाताओं/फर्मों से निविदाएं दिनांक ०4.०2.2०26 दोपहर 12:०0 बजे तक आमन्त्रित की जाती है।विस्तृतविवरण/जानकारी<https://sppp.rajjasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।
UBN- ZUD2526WSOB04264
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरे
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सरे

कार्यालय ग्राम पंचायत छापली जिला राजसमन्द (राज.)
क्रमांक: ग्रापं/लेखा/ई-रेन्डर/2०25-26/31-33 दिनांक :- 24.०1.2०26
निविदा सूचना ०1 -०3/2०25-26
ग्राम पंचायत छापली में निर्माण कार्यों को करवाने लिए नियम 181 के तहत वाणिज्यिक कर विभाग में राजस्थान GST अधिनियम 2०17/GST के अन्तर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठानों/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा का पूर्ण विवरण, शर्तें www.eproc.rajjasthan.gov.in एवं www.sppp.rajjasthan.gov.in Dowanload कर प्राप्त की जा सकती है। साथ ही कार्यालय के नोटिस बोर्ड से कार्य दिवसों में देखी जा सकती हैं।
NIB Code- ZRR2526A0594 and 595, ZRR2526A0598
UBN Code- ZRR2526WSRC00973 to 976, ZRR2526WSR00979
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत छापली

बीफ निर्यातक कंपनियों से चंदा लेने के कांग्रेस विधायक के आरोप पर सदन में हंगामा मचा

सत्ता पक्ष ने विधायक हरिमोहन शर्मा के आरोपों पर गहरी आपत्ति जताते हुए कहा कि, “या तो प्रमाण पेश करें, अन्यथा माफी मांगे, नहीं तो सदन में बोलने नहीं देंगे”

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा के विवादस्पद बयान पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। बुंदी से कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा गौभक्त बनती है, लेकिन बीफ निर्यात करने वाली कंपनियों से चंदा लेकर चुगाव लड़ती है। उनके इस बयान पर सत्तापक्ष ने तत्काल गहरी नाराजगी और आपत्ति जताई। भाजपा विधायकों ने कहा कि यदि उनके पास इसका कोई प्रमाण है तो वे सदन में पेश करें, इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई भाजपा विधायक

खड़े हो गए और कहा कि जब तक प्रमाण नहीं दिया जाता, तब तक उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस पर हरिमोहन शर्मा ने कहा कि गौकशी करने वाली कंपनियों से चंदा लेना एक रिकॉर्डेड फैक्ट है। भाजपा सदस्यों के लगातार हंगामे के बाद सभापति संदीप शर्मा ने कांग्रेस विधायक के इस वक्तव्य को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया। हंगामे के बीच हरिमोहन शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 1671 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिनमें 7 लाख 63 हजार गोवंश हैं और गौशालाओं का सरकार पर करोड़ों रुपए बकाया है। गौवंश भूखे मर रहे हैं और सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन सरकार

■ **हालांकि सभापति संदीप शर्मा ने इस आरोप को सदन की कार्यवाही से बाहर निकालकर मामले को शांत कराया**

उन्हें पैसा नहीं दे रही।

यूडीएच मंत्री से भी हुईं तीखी नौकझोंक

इससे पहले कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खरं के

बीच भी तीखी नौकझोंक हुई। दरअसल हरिमोहन शर्मा ने कहा कि, भाजपा दावा कर रही है कि उसने अपने घोषणापत्र के 70 फीसदी वादे पूरे कर दिए हैं और बाकी 30 फीसदी अगले साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन जनता ने भाजपा को अंता उपचुनाव में आईना दिखाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हार के डर से निकाय व पंचायत चुनाव नहीं करा रही है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। विधायक शर्मा ने नगर पालिका सभापति को 8 बार हटाए जाने का मामला उठाया, जिस पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खरं ने जवाबी हमला बोलते हुए

कहा कि, क्या कांग्रेस चाहती है कि भ्रष्ट सभापति पर कार्रवाई न हो? जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक चुनाव नहीं हो सकते।

इससे पहले हरिमोहन शर्मा ने मनरेगा का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्यपाल से सरकार ने असत्य बुलवाया। महात्मा गांधी विश्वभर में पूजे जाते हैं, लेकिन वैचारिक दृष्टि से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नाथूराम गोडसे की विचारधारा से प्रभावित है, इसलिए महात्मा गांधी का नाम हटाकर राम का नाम लिया गया। इस पर भाजपा सदस्यों ने कहा कि महात्मा गांधी का जितना सम्मान भाजपा ने किया, उतना कांग्रेस ने नहीं किया।

अशोक गहलोत पर 25 करोड़ के घोटाले का आरोप

जयपुर (विसं)। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान भाजपा विधायक अतुल भंसाली ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर 25 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में खुब भ्रष्टाचार हुआ, इनके मंत्री तक जेल गए।

भंसाली ने कहा कि, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के घोटाले अब खुल रहे हैं, इनके मंत्री तक जेल गए। मेरे खुद के जोधपुर शहर में आरयूआईडीपी के काम में 25 करोड़ रुपए का घोटाला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कर लिया। इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा कि, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के राज में जमकर भर्ती परीक्षाओं के पेपरलीक हुए। जबकि हमारी भाजपा सरकार ने बीते 2

सालों में पेपरलीक करने वाले और नकल करके नौकरियां पाने वालों को जेल भेजा। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का वादा किया था, जिसे पूरा किया।

इससे पहले कांग्रेस विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने भाजपा पर एस.आई.आर. (विशेष पुनरीक्षण अभियान) की आड़ में फर्जीवाडा करने का आरोप लगाया। रामकेश मीणा ने कहा कि एस.आई.आर. में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फर्जीवाड़ा किया है। एक-एक कार्यकर्ता ने फर्जी हस्ताक्षर करके 500-500 फॉर्म जमा करवा दिए हैं। जिसने भी फर्जी हस्ताक्षर किए हैं, उसमें एक फॉर्म पर एक साल की सजा है। आप लोगों को 500 साल की जेल होगी। 500 साल तक जेल में रहना चाहते हो क्या। इसकी जांच होगी और हम जांच करवाएंगे।

विधानसभा में गूंजा जयपुर में लेपर्ड के बढ़ते मूवमेंट का मुद्दा

जयपुर (विसं)। राजधानी जयपुर के आबादी इलाकों में लेपर्ड के मूवमेंट का मामला गुरुवार को विधानसभा में गूंजा। मासवीय नगर से भाजपा विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि आबादी इलाकों में लेपर्ड सहित वन्यजीवों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए एक हैल्पलाइन बनेगी। एक महीने में यह 1926 हैल्पलाइन शुरू हो जाएगी। इस हैल्पलाइन पर आबादी इलाकों में लेपर्ड सहित वन्यजीवों के मूवमेंट की जानकारी दी जा सकेगी।

कालीचरण सराफ ने पूरक सवाल पूछते हुए महाराष्ट्र की तर्ज पर सिक्वोएट्री प्रोटोकॉल लागू करने का सुझाव दिया, जिस पर वन मंत्री ने पूरा करने का आश्वासन दिया। वन मंत्री से अपने सवालों के बीच एक और पूरक प्रश्न में विधायक कालीचरण सराफ ने पूछा कि क्या सरकारी यह मानती है कि जयपुर के झालाना,

■ **राज्य सरकार आगले एक माह में हैल्पलाइन नंबर 1926 शुरू करेगी**

आमागढ़ और बीड पीपाड़ इलाकों में बढ़ रही लेपर्ड की संख्या के बीच वनों का क्षेत्र काम हो रहा है।

महाराष्ट्र की तर्ज पर सिक्वोएट्री प्रोटोकॉल लागू करने का सुझाव देते हुए कहा कि, इस व्यवस्था के सहत सूचना मिलने के तत्काल बाद 5 किलोमीटर का क्षेत्र सील कर दिया जाता है, ताकि लोगों के साथ-साथ वन्य जीव की भी सुरक्षा दी जा सके। जिस पर वन मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अन्य राज्यों में इस तरह की हालत सामने आने पर की जाने वाली व्यवस्था का राज्य सरकार परीक्षण करवाएगी और इसी वित्तीय वर्ष में प्रयास होगा कि इसे राजस्थान में भी लागू किया जा सके।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अग्रणी बन रहा राजस्थान : लालाराम बैरवा

भीलवाड़ा/शाहपुरा (कासं)। सोलहवाँ विधानसभा के पंचम सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को शाहपुरा (भीलवाड़ा) से विधायक लालाराम बैरवा ने प्रश्नकाल के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं और प्रदेश को अग्रणी राजस्थान बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।

विधायक बैरवा ने कहा कि पिछले दो वर्षों में एक भी पेपर लीक नहीं होने से युवाओं का भरोसा व्यवस्था पर बढ़ा है। राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरुक्षित वातावरण देने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। किसानों को उनकी फसल का पूरा भुगतान समय पर मिल रहा है तथा प्राकृतिक आपदा या खराबे की स्थिति में पूर्ण मुआवजा दिया जा रहा है।

आदिवासी क्षेत्र में “ग्लोबल गुरुकुलम” के लिए भूमि पूजन

जयपुर (कासं)। भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष त्रुं रिटायर्ड आईएसए एन. पी. सिंह तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष जी. आर. राणा की उपस्थिति में बालोद किया गया विकासखंड अंतर्गत सुदूर आदिवासी ग्राम भेजा जंगली में तथागत “ग्लोबल गुरुकुलम” का विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। यह आयोजन जनजातीय विकास के उद्देश्य से जकवार फाउंडेशन और तथागत ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण शामिल हुए।

भूमि पूजन से पूर्व राजा राव बाबा और कंकालीन माता की पूजा-अर्चना की गई। इसके पश्चात शहीद वीर नारायण सिंह के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए एन. पी. सिंह ने

जयपुर (कासं)। भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष त्रुं रिटायर्ड आईएसए एन. पी. सिंह तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष जी. आर. राणा की उपस्थिति में बालोद किया गया विकासखंड अंतर्गत सुदूर आदिवासी ग्राम भेजा जंगली में तथागत “ग्लोबल गुरुकुलम” का विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। यह आयोजन जनजातीय विकास के उद्देश्य से जकवार फाउंडेशन और तथागत ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण शामिल हुए।

भूमि पूजन से पूर्व राजा राव बाबा और कंकालीन माता की पूजा-अर्चना की गई। इसके पश्चात शहीद वीर नारायण सिंह के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए एन. पी. सिंह ने

मासूम से दुष्कर्म के मुद्दे पर गर्माया सदन

जयपुर (विसं)। विधानसभा में शून्यकाल सभापत होने से ठीक पहले सीकर से विधायक राजेंद्र पारीक द्वारा जिले में 8 वर्षीय मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को उठाए जाने पर सदन का माहौल गरमा गया। मुद्दा उठते ही विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए पोस्टर दिखाने शुरू कर दिए, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई।

विधायक राजेंद्र पारीक ने कहा कि प्रदेश में आए दिन मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं।

सरकार ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन अब उन व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यवस्था की जमीनी हकीकत नहीं परखी जाएगी, तब तक ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना मुश्किल होगा।

कांग्रेस के 5 साल से ज्यादा सड़कें हमने 2 साल में बनाईं : दिया कुमारी

विधानसभा में उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायकों को उनके सवालों पर घेरा

जयपुर (विसं)। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में जितनी दूरी में सड़कें बनाईं, हमने उससे ज्यादा तो बीते 2 सालों में बना दी है। इस दौरान हंगामे की कोशिश करने वाले कांग्रेस विधायकों को भी उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि, सवाल का जवाब देने से पहले ही अग्रेसिव क्यों हो रहे हो? सवाल पूछा है तो उसका जवाब सुनो। कांग्रेस विधायक चेतन पटेल के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि “पिछली सरकार में 5 साल में 13 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनाई गईं। जबकि हमने दो

■ **‘कांग्रेस ने 13 हजार किमी.बनाई थी, हमने 16864 किमी सड़के मात्र 2 साल में बना दी’**

साल में ही 16 हजार 864 किलोमीटर की नई सड़कें बना दीं। दीया कुमारी ने कांग्रेस विधायकों पर पलटवार करते हुए कहा कि पांच साल आपके, दो साल हमारे काम की तुलना सुन लींजिए। पिछली सरकार में 1104 गांव सड़कों से जुड़े। हमने दो साल में 1700 गांव सड़कों से जोड़ दिए हैं। सड़कों के नवीनीकरण पर कांग्रेस के 5 साल में 12300 करोड़

सुनील शर्मा बने कांग्रेस के जयपुर शहर जिलाध्यक्ष

जयपुर । कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के 4 जिलाध्यक्ष गुरुवार देर रात घोषित कर दिए। इनमें सुनील शर्मा को जयपुर शहर जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ से दिग्विजय सिंह, झालावाड़ से वीरेन्द्र सिंह गुर्जर और बारां से हंसराज मीणा को पार्टी जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है।

इस संबंध में के.सी. वेणुगोपाल ने नियुक्ति आदेश जारी किए। बीते लंबे समय से कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां लंबित चल रही थी, परंतु पिछले दिनों कांग्रेस ने इन चार जिलों को छोड़कर अन्य जगहों की नियुक्तियां कर दी थीं।

कार्यक्रम में ग्राम पंचायत की सरपंच शीला यादव, पंच नागेश्वर सलाम, दिनेश यादव, बलराम गोटी स हित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

नई दिल्ली (कासं)। नई दिल्ली के साहित्य आकादमी सभागार में आयोजित गरिमायम समारोह में केरल के वरिष्ठ हिन्दी साहित्यकार ए. अरविंदाक्षन और अरुणाचल प्रदेश की युवा कवयित्री जमुना बीनी को 'तथागत साहित्य सम्मान' से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाकवि निराला की सरस्वती वंदना पर आधारित कथक प्रस्तुति से हुआ। तथागत ट्रस्ट के संरक्षक डॉ. एन. पी. सिंह (पूर्व आईएसएस) ने ट्रस्ट की परिकल्पना, सामाजिक-शैक्षिक कार्यों और उत्तर-दक्षिण भारत के बीच भाषा-संस्कृति संवाद के लक्ष्य को रेखांकित किया। यह सम्मान प्रख्यात साहित्यकार रामरेश्वर मिश्र की स्मृति में प्रदान किया गया। समारोह में वरिष्ठ साहित्यकारों अनामिका, ओम निश्चल, अशोक

मुख्यमंत्री भजनलाल ने किया अच्छे वक्ताओं का सम्मान

विधानसभा में भाजपा विधायकों की हौसला-अफजाई की, लड्डु खिलाए

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को दिनभर चली कार्यवाही के बाद देर शाम एक अलग ही दृश्य देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं विधानसभा परिसर पहुंचे और सक्रिय व प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने वाले भाजपा विधायकों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने अच्छा बोलने वाले विधायकों को लड्डु खिलाकर न सिर्फ उनका सम्मान किया, बल्कि सकारात्मक संसदीय व्यवहार को प्रोत्साहित करने का संदेश भी दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, पंचायतीराज राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम, उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के.के. विश्वनोई सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री से मिलने वालों में विधायक चंद्रभान सिंह, बाबुसिंह राटोड़, छगन सिंह राजपुरोहित, गुरवीर सिंह बराड़, सुभाष

मील, कुलदीप धनकड़, अतुल भंसाली, उदयलाल भडाणा सहित अन्य भाजपा विधायक शामिल रहे। सभी ने विधानसभा की कार्यवाही, जनहित के मुद्दों और सरकार की नीतियों को प्रभावी रूप से सदन में रखने पर चर्चा की।

दिलचस्प बात यह रही कि इस दौरान कांग्रेस के विधायक ललित यादव, जाकिर हुसैन और डूंगरराम गेदर ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसे सदन के भीतर सीहार्दपूर्ण और सकारात्मक राजनीतिक माहौल के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों से संवाद करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सदन में सार्थक, तथ्यपरक और जनहित से जुड़ी चर्चा बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो विधायक जनता की आवाज को मजबूती से सदन में रखते हैं, उनका प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की इस पहल को भाजपा विधायकों के मनोबल को बढ़ाने और विधानसभा की कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर का मुद्दा विधानसभा में गूंजा

विधायक बालमुकुंददाचार्य ने कहा “ ध्वनि प्रदूषण से लोग परेशान, विद्यार्थियों की पढ़ाई हो रही बाधित ”

जयपुर (विसं)। हवामहल विधायक बालमुकुंददाचार्य ने गुरुवार को विधानसभा में धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया। शून्यकाल में बोलते हुए विधायक बालमुकुंददाचार्य ने कहा कि कई धर्म स्थलों, विशेषकर मीनारों की ऊंचाई पर लगे लाउड स्पीकरों से अत्यधिक तेज आवाज में प्रसारण किया जाता है। सुबह करीब 4 बजे से ही लाउड स्पीकर बजने लगते हैं, जिससे आमजन की नींद में खलल पड़ता है। यह न केवल लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा मस्जिदों में लाउड स्पीकर का आवाज कम करने का आग्रह करने पर कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है और धर्म विशेष के कुछ लोग झगड़े पर उतर आते हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। रमजान के दौरान अतिरिक्त लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं और आवाज और अधिक तेज कर दी जाती है, जिससे बीमार लोगों, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता है।

विधायक बालमुकुंददाचार्य ने कहा कि इस समस्या को लेकर कई बार



विधायक बालमुकुंददाचार्य

संबंधित विभागों में शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तेज आवाज के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जो बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक है। उन्होंने सरकार से मांग की कि लाउड स्पीकरों के उपयोग को लेकर स्पष्ट नियम बनाए जाएं और उनकी आवाज की तीव्रता तय की जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके और साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहे।

डीआरआई ने 17.6 किलो हाइड्रोपोनिक वीड पकड़ा

जयपुर (कासं)। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने 17.6 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (गाँजा) के साथ जयपुर एयरपोर्ट पर एक यात्री को गिरफ्तार किया। डीआरआई अधिकारियों ने यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की। बताया जा रहा है कि 29 जनवरी को आबू धाबी से जयपुर पहुंची फ्लाइट में एक यात्री के पास यह हाइड्रोपोनिक वीड (गाँजा) मिला। हैदराबाद निवासी यह यात्री बैंकों के पास धाबी होते हुए जयपुर आया था। अधिकारियों को यात्री के ट्रॉली बैग से 17.6 किलो हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 6.5 करोड़ रुपये है। यह जयपुर एयरपोर्ट पर डीआरआई की सबसे बड़ी कार्यवाही है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) जयपुर ने नशे की तस्करी सिंडिकेट से जुड़े हैदराबाद



■ **जयपुर एयरपोर्ट पर आबू धाबी से आया यात्री गिरफ्तार**

■ **आरोपी के कब्जे से जऊ गांजे की कीमत 6.5 करोड़ रु. है**

निवासी एक युवक को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।

जोधपुर ने रचा पर्यटन क्षेत्र में नया इतिहास

वर्ष 2025 में आए 38 लाख से अधिक पर्यटक

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 38 लाख से अधिक पर्यटकों के आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह अभूतपूर्व उपलब्धि जोधपुर की वैश्विक स्तर पर एक ‘कम्प्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन’ के रूप में नई पहचान का सशक्त प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रसन्नता जताते हुए कहा “जोधपुर बना कम्प्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन”**

डबल इंजन की सरकार के “विकास भी-विरासत भी” के संकल्प का सुपरिणाम है। उन्होंने कहा कि

केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से पर्यटन अवसरंचना के सुदृढ़ीकरण, ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण, बेहतर कनेक्टिविटी, स्वच्छता, सुरक्षा तथा पर्यटक-सुविधाओं के विस्तार से जोधपुर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हुआ है। शर्मा ने कहा कि जोधपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरें, लोककला और पारंपरिक हस्तशिल्पदेश-विदेश

के पर्यटकों को निरंतर आकर्षित कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप पर्यटन क्षेत्र में सतत वृद्धि दर्ज की जा रही है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की पहल पर गत वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन जोधपुर में किया गया, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर शहर की पहचान और अधिक सुदृढ़ हुई तथा पर्यटन को नई दिशा मिली।

कार्यक्रम में ग्राम पंचायत की सरपंच शीला यादव, पंच नागेश्वर सलाम, दिनेश यादव, बलराम गोटी स हित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

नई दिल्ली (कासं)। नई दिल्ली के साहित्य आकादमी सभागार में आयोजित गरिमायम समारोह में केरल के वरिष्ठ हिन्दी साहित्यकार ए. अरविंदाक्षन और अरुणाचल प्रदेश की युवा कवयित्री जमुना बीनी को 'तथागत साहित्य सम्मान' से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाकवि निराला की सरस्वती वंदना पर आधारित कथक प्रस्तुति से हुआ। तथागत ट्रस्ट के संरक्षक डॉ. एन. पी. सिंह (पूर्व आईएसएस) ने ट्रस्ट की परिकल्पना, सामाजिक-शैक्षिक कार्यों और उत्तर-दक्षिण भारत के बीच भाषा-संस्कृति संवाद के लक्ष्य को रेखांकित किया। यह सम्मान प्रख्यात साहित्यकार रामरेश्वर मिश्र की स्मृति में प्रदान किया गया। समारोह में वरिष्ठ साहित्यकारों अनामिका, ओम निश्चल, अशोक

वरिष्ठ हिन्दी साहित्यकार ए. अरविंदाक्षन और अरुणाचल की युवा कवयित्री जमुना बीनी को 'तथागत साहित्य सम्मान' से नवाजा गया।

वाजपेयी, चंद्रकांता सहित अनेक विद्वानों ने दोनों रचनाकारों के साहित्यिक योगदान पर विचार साझा किए। ए. अरविंदाक्षन की कृति 'धड़कनों के भीतर जाकर' और जमुना बीनी के संग्रह 'जब आदिवासी गाता है' के माध्यम से भाषाई संवेदनाओं, आदिवासी चेतना और मानवीय मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति सामने आई। यह आयोजन न केवल हिन्दी साहित्य, बल्कि समूचे भारतीय साहित्य में संवाद, संवेदना और मानवीयता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने केन्द्रीय कृषि मंत्री का आभार जताया

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजस्थान को मटीरियल कंपोनेंट के तहत 825 करोड़ रूपए की राशि जारी की थी

नई दिल्ली/जयपुर, 29 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार देर रात को नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस अवसर पर शर्मा ने राजस्थान के लिए मटेरियल कंपोनेंट के अंतर्गत 825 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी किए जाने पर

■ **शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को इस मद में अग्रिम राशि जारी करने का भी आश्वासन दिया है।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और विभिन्न योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तृत चर्चा की।

‘अमेरिका और नाटो के बीच ग्रीनलैंड को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ’

डेनमार्क की प्र.मंत्री मेटे फ्रैंडरिकसेन ने फ्रांस के टीवी चैनल से वार्ता के दौरान दावा किया

पेरिस, 29 जनवरी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने बुधवार को इस बात से इनकार किया कि नॉर्थ अटलंटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (नाटो) और अमेरिका के बीच ग्रीनलैंड मुद्दे पर कोई समझौता हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में दावा किया था कि उन्होंने ग्रीनलैंड पर नाटो के साथ एक समझौता किया है। जब फ्रांस-2 टीवी चैनल के साथ साक्षात्कार में फ्रेडरिकसेन से इस संबंध में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, "यह कोई

■ **फ्रैंडरिकसेन ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रैंडरिक नील्सन के साथ फ्रांस की यात्रा पर आयी हैं।**

समझौता नहीं है।" फ्रेडरिकसेन ने साक्षात्कार में कहा कि असल में एक राज्य संप्रभु होता है। उसकी सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और दूसरे लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। फ्रेडरिकसेन ने कहा कि अगर ग्रीनलैंड में सैन्य साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो सब कुछ रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि "यह उन सभी चीजों के खिलाफ होगा जो हम दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से बना रहे हैं।" फ्रेडरिकसेन बुधवार को ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन के साथ फ्रांस पहुंचीं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ बढ़ ता तनाव पूरे यूरोप के लिये एक रणनीतिक चेतावनी है। साथ ही उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ फ्रांस की एकजुटता की बात दोहराई।

राजस्थान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) वास्तव में एक स्वतंत्र व्यक्ति राज्यसभा सांसद बने, जो किसी भी गुट, समूह या नेता से जुड़ा न हो। क्या उनका इशारा पवन खेड़ा की ओर था, जो राज्यसभा जाने की कोशिश कर रहे हैं और अशोक गहलोत के क़रीबी माने जाते हैं, हालाँकि स्वयं गहलोत भी राज्यसभा नामांकन के लिए प्रयासरत हैं? आखिरकार, राज्यसभा के लिए चयन का फैसला पार्टी नेतृत्व के हाथ में है और यह उसका विशेषाधिकार है। पार्टी जल्द ही नगर निकाय और स्थानीय निकाय चुनावों का सामना करना पड़ेगा और राज्य नेतृत्व का कहना है कि वे इन चुनावों में जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं।

शशि थरूर, राहुल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बनने, को पूरा करने के लिए किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, तो यह चिंता का विषय है। उदाहरण देते हुए शशि थरूर ने राहुल गांधी को बताया कि जब उन्होंने केरल में एक बैठक को संबोधित किया, तो उन्होंने उनका नाम तक नहीं लिया, जबकि वे मंच (डायस) पर मौजूद थे। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि उन्हें एक पर्वी दी गई थी, जिसमें कुछ नाम लिखे थे, और उन्होंने वही नाम पढ़ दिए। नेताओं का कहना है कि यह वेणुगोपाल की शरारत थी। सूत्रों के मुताबिक, शशि थरूर ने राहुल गांधी से केवल दो बातें कहीं। पहली, राहुल को उन पर भरोसा होना चाहिए; और दूसरी, उन्हें संसद में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। दोनों ही मांगों पर राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसा किया जाएगा। इसके साथ ही, राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को निर्देश दिया कि वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सूचित करें कि शशि थरूर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) की सभी बैठकों में आमंत्रित किया जाए।

इतना ही नहीं, आगामी विधानसभा चुनावों के लिए केरल में कांग्रेस की अभियान समिति और प्रचार समिति की जिम्मेदारी भी शशि थरूर को सौंप दी गई है। राहुल गांधी ने थरूर को शिकायतों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वस्त

(प्रथम पृष्ठ का शेष) नियंत्रण रखना चाहिए। अर्थशास्त्र की भाषा में इसका मतलब है कि बेहतर भविष्य और आगे चलकर अधिक उपभोग के लिए आज की खपत को कम कर बचत बढ़ाई जाए। अगर इस तरह के सुझाव को अमल में लाया जाता है, और जब मुख्य आर्थिक सलाहकार खुद ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा क्यों न हो, लेकिन इसका सीधा विकास नहीं, बल्कि मौजूदा समीय में मंदी होगा। खुद सीईए ने दिखाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती घरेलू खपत के सहारे आगे बढ़ रही है, जो मांग और आर्थिक गतिविधियों को गति दे रही है। उस पर ब्रेक लगाना विनाश और मंदी को बुलाना देना होगा। अगर कुछ करना ही है तो घरेलू

■ **राहुल गांधी ने तुरंत प्रभाव से थरूर को आगामी चुनाव के लिए गठित अभियान समिति व प्रचार समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया।**

■ **थरूर ने एक आग्रह यह भी किया कि उन्हें संसद में बोलने का मौका दिया जाए।**

किया कि उनका समाधान किया जाएगा। इस बैठक को शशि थरूर की एक तरह की जीत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि यह समझ आगामी विधानसभा चुनावों तक बनी रहेगी।

नालों की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अलग उच्च न्यायालयों के इस मामले पर अलग-अलग विचार थे कि कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मामले में 10 लाख रुपये दिए, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूसरे मामले में 30 लाख रुपये दिए।

बब्बर खालसा के दो आतंकवादी गिरफ्तार

चंडीगढ़ 29 जनवरी। पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश की पुलिस के साथ एक बड़ी कार्रवाई में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन रमाके के सिलसिले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के ऑपरेटिव हरविंदर रिंड़ा और पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा समर्थित एक नाकॉ-टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने गुरुवार को बताया कि मॉड्यूल के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक आईडी बरामद किया गया है। यह ऑपरेशन हिमाचल प्रदेश की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शमशेर सिंह उर्फ शेख और प्रदीप सिंह उर्फ दीपू, दोनों निवासी राहों, के तौर पर हुई है।

इकोनॉमिक सर्वे ने भी ...

खपत को बनाए रखा जाना चाहिए, ताकि निर्यात में होने वाली किसी भी कमी की भरपाई की जा सके। बेशक, सीईए के तर्क के पीछे की सोच साफ है। विकास के लिए निवेश चाहिए और निवेश बचत से ही आ सकता है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में घरेलू बचत की कमी को विदेशी बचत से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी, ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, घरेलू कैपिटल, मार्केट में ज्यादा फंड का फ्लो, विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए सरकारी ट्रेजरी मार्केट खोलना, ये सब घरेलू बचत की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन और कम महंगाई दर को देखते हुए सरकार के पास विस्तारवादी नीतियां अपनाने की गुंजाइश है। यह बढ़े

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम और इन क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश के जरिए होना चाहिए। इस तरह के कदम से न केवल कुल डिमांड बढ़ेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर ज्यादा रोजगार पैदा होने से ग्रोथ और इन्कम जैनेरेशन का मल्टीप्लायर इफैक्ट भी शुरू हो सकता है।

सुप्रीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) से पार्टी को राजनीतिक नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि ऊंची जातियों में नाराजगी बढ़ी, और यह सड़कों पर प्रदर्शनों के रूप में सामने आई है। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को होगी।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 जनवरी। राष्ट्रावादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की श्रद्धांजलि लिखना अभी जल्दबाज़ी होगी, लेकिन विमान दुर्घटना में अजित पवार की अचानक हुई मृत्यु निस्संदेह पार्टी के दोनों गुटों के साथ-साथ, उस परिवार के लिए भी लगभग घातक झटका है, जिसने पिछले चार दशकों से पश्चिमी महाराष्ट्र की शुगर बैल्ट और उसकी समृद्ध सहकारी संस्थाओं की राजनीति पर नियंत्रण रखा है। इससे बदतर समय नहीं हो सकता था। अजित पवार का निधन ऐसे समय में हुआ है। वर्ष 2023 में हुए विभाजन के बाद, एनसीपी गंभीर दौर से गुजर रही है। एक विभाजन ने पार्टी को ही नहीं बल्कि, महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक परिवारों में से एक को भी विभाजित कर दिया था, जहाँ भतीजा, चाचा के आमने-सामने आ गया और पार्टी के पितामह शरद पवार की सावधानी से बनाई गई उत्तराधिकार योजना उलट गई थी। यदि अजित पवार जैसी बड़ी क्षति

समीर वानखेडे का मुकदमा खारिज

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा नेटफिलक्स सीरीज द बेड्स ऑफ बॉलीवुड में कथित रूप से चित्रित किए जाने के संबंध में दायर

■ **भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी समीर वानखेड़े ने नेटफिलक्स सीरीज “द बेड्स ऑफ बॉलीवुड” के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी। जिसे कोर्ट ने क्षेत्राधिकार का अभाव बताकर खारिज कर दिया।**

मानहानि के मुकदमे को क्षेत्राधिकार के अभाव का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय इस मामले का निर्णय करने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है और वानखेड़े को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी।

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को उन याचिकाओं के समूह पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिनमें चुनाव आयोग (ईसीआई) के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की वैधता को चुनौती दी गई थी। न्यायालय इस बात की जांच कर रहा है कि क्या चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 326, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत यह अधिकार है कि वह एसआईआर को वर्तमान स्वरूप में संचालित कर सके। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ

पुनः आयोजित जेई भर्ती 2021 का पेपर भी लीक हुआ था

जाँच में सामने आया कि निरस्त परीक्षा के सफल अभ्यर्थी पुनः आयोजित परीक्षा में भी संदिग्ध रूप से सफल हुए

जयपुर, 29 जनवरी। कनिष्ठ अभियंता (जेई) संयुक्त भर्ती परीक्षा-2020 के पेपर लीक होने के बाद निरस्त की गई परीक्षा के पुनः आयोजन में भी गंभीर अनियमितता सामने आई है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की जांच में यह खुलासा हुआ है कि 12 सितंबर 2021 को पुनः आयोजित कनिष्ठ अभियंता (सिविल) भर्ती परीक्षा-2021 का पेपर भी लीक कर दिया गया था। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल ने बताया कि दिसंबर 2020 में आयोजित कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा-2020 को पेपर लीक होने के कारण निरस्त किया गया था, जिस संबंध में सांगानेर थाने में केस दर्ज किया गया था। उसी केस की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि निरस्त परीक्षा में सफल अभ्यर्थी पुनः आयोजित परीक्षा में भी

संदिग्ध रूप से सफल हुए। जांच में यह उजागर हुआ कि पुनः आयोजित परीक्षा में भी पेपर माफिया सक्रिय था और पेपर लीक हुआ था। इस संबंध में 19 जनवरी 2026 को थाना एसओजी में नया केस दर्ज किया गया। एसओजी ने इस मामले में जगदीश बिश्नोई निवासी सांचौर जिला जालौर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर परीक्षा से पहले पेपर लीक किया। जांच में यह भी सामने आया कि गणपतलाल बिश्नोई निवासी सांचौर जिला जालौर, जो वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है, को भी

अवैध तरीके से परीक्षा उतीर्ण कराई गई। वह इस भर्ती में मेरिट क्रमांक 12 पर चयनित हुआ तथा बाद में उसे पदोन्नत भी किया गया। एसओजी ने बताया कि इससे पहले सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक होने के तथ्य भी सामने आ चुके हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भर्ती परीक्षाओं की शुचितता को प्रभावित करने वाला एक संगठित गिरोह सक्रिय है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड लिया गया है। एसओजी द्वारा पूरे नेटवर्क की पहचान, अन्य संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी तथा अवैध रूप से अर्जित लाभ को निरस्त कराने की कार्रवाई जारी है।

एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि क्या चुनाव आयोग के पास संविधान के तहत एसआईआर आयोजित करने का अधिकार है

■ **इस मामले में नवम्बर 2025 से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।**

ने नवंबर 2025 से चल रही व्यापक सुनवाई के बाद मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अधिकांश याचिकायें पिछले वर्ष जून में तब दायर की गयी थीं, जब चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्णय किया था। गैर-सरकारी संगठनों, राजनीतिक नेताओं और व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं सहित 13 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय का रुख किया है। इनमें मुख्य याचिकाकर्ता के रूप में

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), पीयूसीएल, योगेंद्र यादव, महुआ मोइत्रा (तृणमूल कांग्रेस सांसद), मनोज झा (आरजेडी सांसद), के.सी. वेणुगोपाल (कांग्रेस सांसद) और सुप्रिया सुले (एनसीपी-एनपी) आदि शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एसआईआर एक अप्रत्यक्ष "एनआरसी जैसी प्रक्रिया" है, जो प्रभावी रूप से चुनाव आयोग को नागरिकता सत्यापन के लिए एक वास्तविक प्राधिकरण में बदल देती है। उन्होंने तर्क दिया कि मतदाता पात्रता संबंधी शंकाओं का समाधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के अनुसार ही किया जाना चाहिए, जिसमें मतदाता सूची से अयोग्य घोषित किए जाने के विशिष्ट

आधार बताए गये हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल, डॉ. ए.एम. सिंघवी, गोपाल शंकरनारायणन, शादान फरासत, पी.सी. सेन और राजू रामचंद्रन, साथ ही अधिवक्ता प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर, निज़ाम पाशा और शाहरुख आलम विभिन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुये। याचिकाओं का विरोध करते हुये, चुनाव आयोग ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया को केवल चुनावी उद्देश्यों के लिए ही देखा जाना चाहिए, न कि निर्वासन या अन्य परिणामों के लिए नागरिकता निर्धारित करने की प्रक्रिया के रूप में। आयोग ने एसआईआर को एक "उदार, सौम्य" प्रक्रिया बताया, जिसमें किसी भी प्रकार की कठोर या दबावपूर्ण जांच शामिल नहीं है।

अजित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उल्लेखनीय है कि जिस समय हादसा हुआ उस समय बारामती में मौसम साफ था और दृश्यता 3,000 मीटर थी। हवा शांत थी। बारामती एयरफील्ड पर उतरते समय पहले दो बार पायलट ने रनवे नजर नहीं आने की बात कही थी जिसके कारण विमान उतर नहीं पाया। तीसरी बार में पायलट ने कहा कि उसे रनवे दिख रहा है और विमान को सुबह 8.43 पर उतरने की अनुमति प्रदान कर दी गयी। इसके बाद 8.44 बजे एटीसी ने रनवे 11 के एक छोर पर आग की लपटें देखीं। कमांड पायलट के पास 1,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था। को-पायलट के पास भी लगभग 1,500 घंटे का उड़ान अनुभव था।

बांग्लादेश के 99 विस्थापित हिंदू परिवारों का यूपी में पुनर्वास होगा

लखनऊ, 29 जनवरी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से विस्थापित 99 हिंदू परिवारों के पुनर्वास को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि ये परिवार फिलहाल मेरठ जिले के मवाना क्षेत्र के गंगला गोसाई गांव में रह रहे थे और यह पुनर्वास राष्ट्रीय हरीत अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में किया जा रहा है।

■ **उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मोहर लगाई**

■ **इन परिवारों को कानपुर देहात के रसूलाबाद व ताजपुर तरसौली गाँव में बसाया जाएगा।**

खन्ना ने बताया कि पुनर्वास योजना के तहत 50 परिवारों को कानपुर देहात

जिले की रसूलाबाद तहसील के भैंसाया गांव में 11.1375 हेक्टेयर (27.51 एकड़) भूमि पर बसाया जाएगा, जबकि शेष 49 परिवारों को ताजपुर तरसौली गांव में 10.530 हेक्टेयर (26.01 एकड़) भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यह भूमि पुनर्वास विभाग के नाम दर्ज है। प्रत्येक परिवार को 0.50 एकड़ भूमि 30 वर्ष की लीज पर दी जाएगी, जिसे दो बार 30-30 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। इस प्रकार अधिकतम 90 वर्षों तक लीज की व्यवस्था होगी, जो निर्धारित प्रीमियम अथवा लीज रेंट के भुगतान पर प्रदान की जाएगी।

एन सी पी के भविष्य पर सवालिया निशाल लगा दिया है अजित पवार की अचानक मौत ने

पर, इसे एन सी पी का अंत मान लेना अभी जल्दबाज़ी होगा

■ **अजित की मौत ऐसे समय में हुई है, जब 2023 में विभाजित हुई पार्टी बड़े नाजुक दौर से गुजर रही थी।**

■ **अगर राजनीति के धुरंधर शरद पवार अपनी पार्टी को इस भारी क्षति से उबारने के लिए कोई चमत्कारिक समाधान नहीं कर पाए तो एन सी पी के खाली स्थान पर भाजपा कब्जा कर लेगी।**

■ **अभी सबसे बड़ा मुद्दा अजित पवार गुट के 41 विधायकों का है. यह भी चर्चा है कि भाजपा नेतृत्व उन सभी को अपनी पार्टी में शामिल कर सकता है।**

के बाद, शरद पवार अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए आखिरी बार भी कोई चमत्कार नहीं कर पाते, तो भाजपा की मशीनरी निश्चित रूप से एनसीपी द्वारा खाली किए गए स्थान पर कब्जा करने आगे बढ़ेगी। पहली बात, दोनों गुट (एक अजित पवार के नेतृत्व में और दूसरा शरद पवार के नेतृत्व में) हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों में पुणे और पिंपरी-चिंचवड जैसे अपने गढ़ों में लगभग सफ़ाए के सदमे से अब तक उबर नहीं पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दोनों पर कब्जा कर लिया और उसकी जबरदस्त जीत दोनों एनसीपी गुटों के

लिए, और संभवतः पवार परिवार के लिए भी, अस्तित्व का संकेत खड़ा करता है। दूसरी बात, दोनों गुटों के पुनर्मिलन की योजनाएँ अब अधर में लटक गई हैं। सीट-बंटवारे को लेकर भाजपा से मतभेदों के बाद, नगर निगम चुनावों से पहले विलय के लिए अजित पवार ही अपने चाचा के पास गये थे। दोनों ने चरणबद्ध तरीके पर सहमति जताई थी। पहला कदम नगर निगम चुनावों के लिए गठबंधन बनाना था। अगला कदम आगामी जिला परिषद चुनाव एक ही चुनाव चिह्न पर लड़ना था। चाचा-भतीजे इस पर सहमत थे कि वे "घड़ी"

का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करेंगे, जिसे चुनाव आयोग ने शरद पवार से लेकर अजित पवार की पार्टी को दे दिया था। इसके बाद, पुनर्मिलन महज औपचारिकता रह जाना था, जिसे स्थानीय चुनाव पूरे होने के बाद किया जाना था। अब यह कहना मुश्किल है कि यह प्रक्रिया पूरी होगी या नहीं। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले हफ्तों में अजित पवार के 41 विधायक किस दिशा में जाते हैं। अजित के प्रभावशाली नेतृत्व के बिना वे लगभग अनाथ और दिशाहीन हो गए हैं। वर्ष 2022 से महाराष्ट्र की पार्टियों में जिस तरह टूट-फूट हुई है, उसे देखते

हुए इस बात की प्रबल संभावना है कि वे या तो अलग-अलग दिशाओं में बिखर जाएँ या फिर भाजपा उन्हें अपने में समाहित कर ले। अजित पवार के अप्रत्याशित निधन से भाजपा के सामने अवसर भी है और चुनौतियाँ भी। उनकी एनसीपी, एकनाथ शिंदे की सेना के मुक़ाबले संतुलनकारी शक्ति के रूप में उपयोगी साबित हुई थी। वस्तुतः, अजित पवार के बिना शर्त समर्थन के चलते ही, शिंदे की नाराजगी और दबाव को राजनीति के बावजूद, देवेन्द्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ़ हुआ था। इसके बाद जब-जब शिंदे ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, अजित पवार उन्हें लाइन पर लाने के काम आए। एक अर्थ में, फडणवीस और भाजपा ने एक क़ौमती सहयोगी को दिया है। फिर भी, अजित पवार की मृत्यु को महाराष्ट्र में भाजपा के दीर्घकालिक लक्ष्य, एकमात्र प्रभुत्वशाली शक्ति बनने और अगले विधानसभा चुनाव में अपने दम पर सरकार बनाने, को हासिल करने के लिहाज से अनुकूल भी माना जा सकता है।